RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 1 मासिक पत्रिका
25 जनवरी 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

भारत की विरासत को संजोता श्रीराम मंदिर

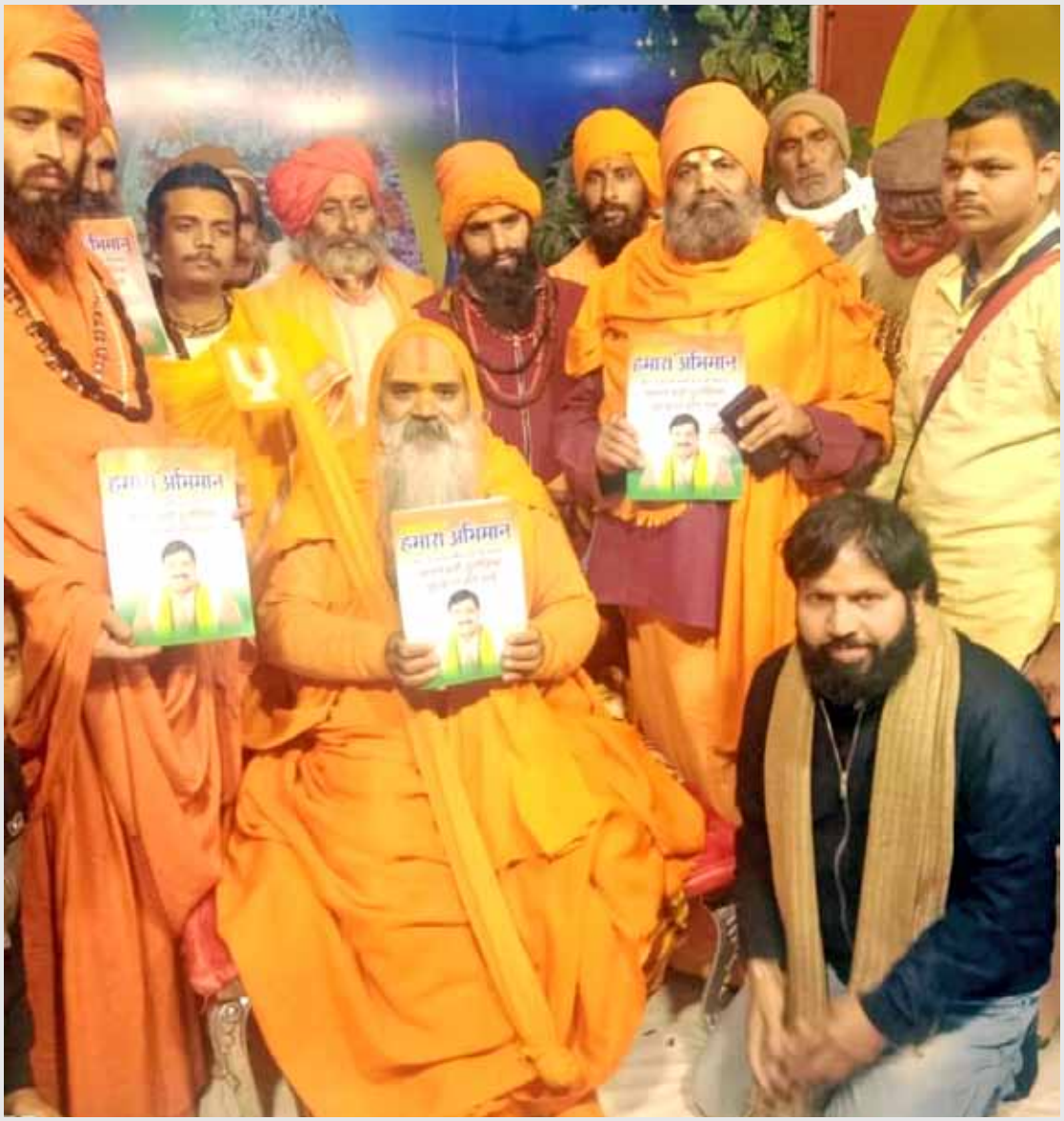

अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास

लोकायुक्त एस पी आदरणीय भाई श्री रामेश्वर यादव जी के साथ हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका के संपादक मनोज चतुर्वेदी

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 जनवरी 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
देश	.....	08-09
प्रदेश	.....	10
इन्दौर	.....	11
देश-विदेश	.....	13
प्रदेश	.....	14
उज्जैन	.....	16
देश	.....	18-19
2023	.....	24
2024	.....	25
प्रदेश	.....	26
इन्दौर	.....	27
भोपाल-इन्दौर	.....	28
देश	.....	29
देश	.....	30
प्रदेश	.....	31
प्रदेश	.....	32-33
देश-प्रदेश	.....	34-35
देश	.....	36
प्रदेश	.....	37
आर्थिक	.....	40
शिक्षा	.....	44
अयोध्या	.....	45
मौसम	.....	46
ग्लैमर	.....	47-48

48

दीया ने किए दिलचस्प खुलासे, बोलीं- 'फर्जी खबरों से जूझते हैं कलाकार'

संपादकीय

भारत : देश में सांस्कृतिक धरोहरों को दिलाया जा रहा है उचित स्थान

वर्ष 2014 के बाद से भारत में सांस्कृतिक धरोहरों को संवारने का कार्य बहुत सफल तरीके से सम्पन्न किया जा रहा है। इसी का प्रमाण आज प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के रुप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार के प्रयास भारत के अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को विकसित करने के लिए भी किए गए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में सम्पन्न होने जा रही है। पिछले लगभग 500 वर्षों के लम्बे संघर्ष के पश्चात श्रीराम लला टेंट से निकलकर एतिहासिक भव्य श्रीराम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे देश का वातावरण राममय हो गया है। न केवल भारत के नागरिकों में बल्कि अन्य कई देशों में भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले नागरिकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अमेरिका के कई बड़े शहरों में प्रभु श्रीराम के बहुत बड़े आकार के होर्डिंग लगाए गए हैं। पूरे विश्व में ही एक तरह से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज सनातनी हिंदुओं के लिए यह एक एतिहासिक एवं गर्व करने का पल है क्योंकि प्रभु श्रीराम का मंदिर भारतीयों के लिए सदियों से एक सांस्कृतिक धरोहर रहा है और अब पुनः प्रभु श्रीराम के मंदिर को सांस्कृतिक धरोहर के रुप में उचित स्थान दिलाया जा रहा है, इसके लिए पिछले 500 वर्षों के दौरान लाखों भारतीयों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। वर्ष 2014 के बाद से भारत में सांस्कृतिक धरोहरों को संवारने का कार्य बहुत सफल तरीके से सम्पन्न किया जा रहा है। इसी का प्रमाण आज प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के रुप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार के प्रयास भारत के अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को विकसित करने के लिए भी किए गए हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कठोर मौसम बाधा न बन पाए, इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा बाबा अमरनाथ गुफा तक 110 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें 11 किलोमीटर लम्बी एक सुरंग भी शामिल है। अभी तक श्रीनगर से बाबा अमरनाथ गुफा तक यात्रा करने में लगभग 3 दिन का समय लगता था किंतु इस नए विकसित किए जा रहे सड़क मार्ग के पश्चात केवल 8 से 9 घंटे के बीच का समय लगेगा।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

राम मंदिर: भारतीय सभ्यता के नायक... रामचरितमानस का अनुपम उपहार

रामचरितमानस के राम भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान के नायक हैं। वह तुलसीदास ही हैं, जिन्होंने राम के प्रति अटूट श्रद्धा की नींव रखी। इस तरह समाज को रामचरितमानस का अनुपम उपहार देकर तुलसीदास भारतवर्ष के भविष्य की भी रचना कर गए हैं। भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में एक ऐसा नाम है, जो मुगल काल में सनातन पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मूर्ति के रुप में उभरता है, वह है गोस्वामी तुलसीदास का। उनके महाकाव्य रामचरितमानस ने सनातन धर्म का उस समय पुनर्जागरण किया, जब भारत में मुगलों की तूती बोलती थी। आज के दिन, जब राम की जन्मस्थली अयोध्या में पांच सौ वर्षों बाद राम मंदिर सनातन धर्म की महिमा का प्रतीक बन गया है, जब चारों दिशाएं 'जय श्रीराम' के नारों और राम भजनों से गूंज रही हैं और हवाओं में केसरिया रंग घुला है, तब यह आवश्यक हो गया है कि हम हर्ष-उल्लास के इस अद्भुत कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास को भी अपनी स्मृतियों में संजोएं, जिन्होंने राम को देश के कण-कण में व्याप्त कर दिया, उन्हें भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े नायक के रुप में जन-जन के रोम-रोम में स्थापित कर दिया। तुलसीदास का असाधारण योगदान न केवल उनके कृतित्व की साहित्यिक प्रतिभा में है, वरन भारतीय समाज के ताने-बाने पर मुगल प्रभाव को थोपने के विरुद्ध उनके दृढ दृष्टिकोण में भी है। तुलसीदास ने जान-बूझकर मुगलों की भाषा और अपसंस्कृति के प्रतीकों को रामचरितमानस से बाहर रखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। माना जाता है कि उन्होंने 1574 और 1576 के बीच इस कृति का सृजन किया। हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों के हिसाब से इसका सटीक समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, पर सनातन मान्यताओं को अविरल रुप से सींचती रामचरितमानस एक कालजयी और श्रद्धेय कृति बनी हुई है और निस्संदेह विश्व में सर्वाधिक पढ़ी और गाई जाने वाली महाकाव्यात्मक रचना भी।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

भारत की विरासत को संजोता श्रीराम मंदिर

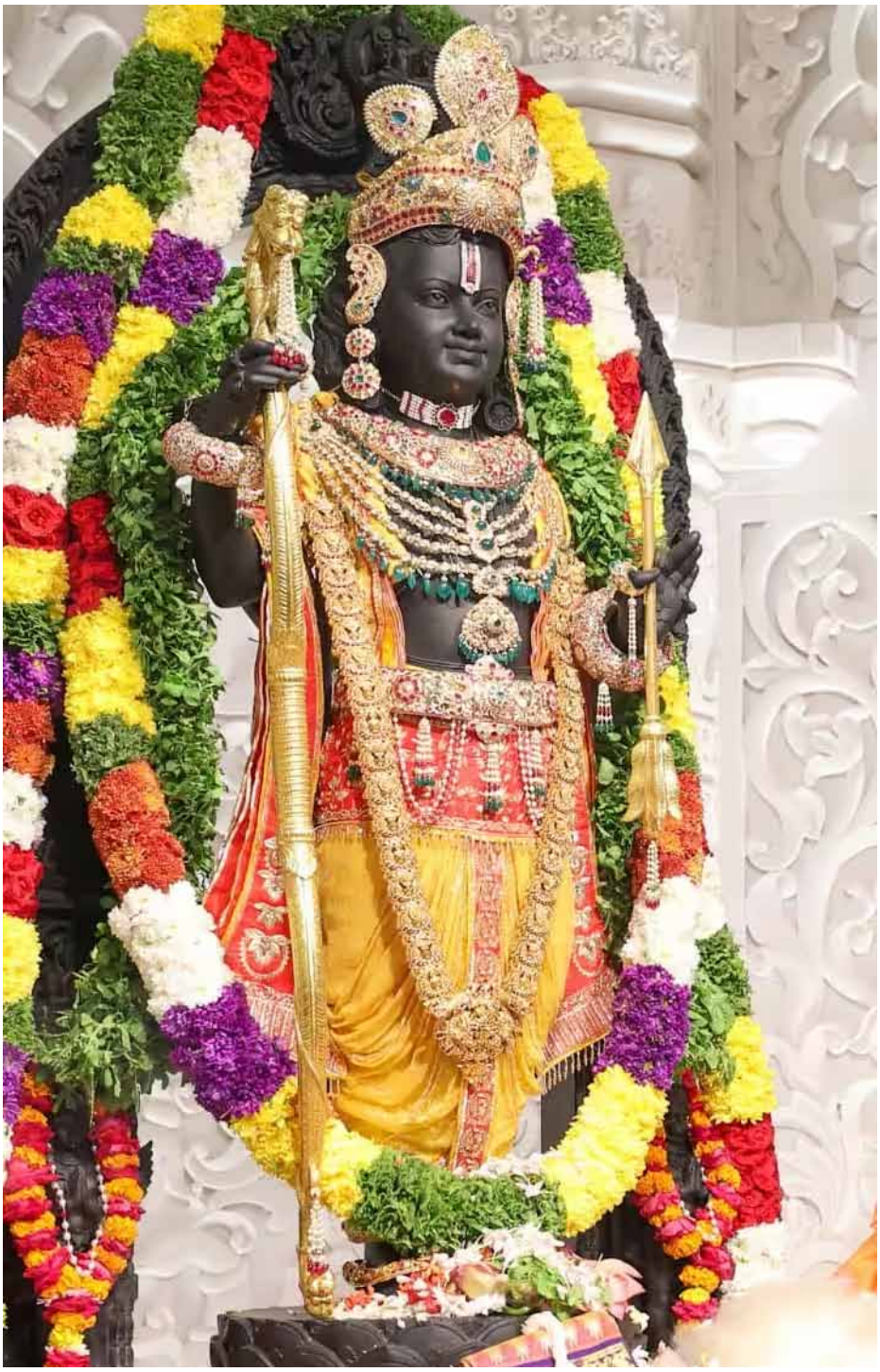

राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति के उत्थान में प्रमुख स्थान रखता है। हमारा देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में न केवल जकड़ा रहा बल्कि विदेशी आक्रांताओं ने केवल भारत को लूटा अपितु उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की भी कोशिश की। राम मंदिर से देश की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एकता और अखंडता सुदृढ़ होगी एवं समस्त विश्व में भारत विश्व बन्धुत्व का संदेश देगा और भारतीय जनमानस का आत्मबल बढ़ेगा।

राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति के उत्थान में प्रमुख स्थान रखता है। हमारा देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में न केवल जकड़ा रहा बल्कि विदेशी आक्रांताओं ने केवल भारत को लूटा अपितु उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की भी कोशिश की। प्राचीन काल में मंदिरों केवल पूजा स्थल ही नहीं थे बल्कि गुरूकुल जैसा वातावरण रहता था। इन गुरुकुलों में शिष्य मंदिर की भूमि पर न केवल खेती करते बल्कि वहीं सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक सभी आयामों के कला कौशल का ज्ञान प्राप्त करते थे।

श्रीराम मंदिर नए भारत का प्रतीक होगा जो भारत को एक बार फिर विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता देगी। श्रीराम चंद्र की नगरी अयोध्या बाकी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। श्रीराम मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। हम हिन्दुओं के श्रद्धेय भगवान श्रीराम मर्यादा पुरूषोत्तम थे, आज विश्व में शांति की स्थापना के लिये उसी मर्यादा की जरूरत है। राम का चरित्र अनुकरणीय है और उनका जीवन ही विश्व का उत्थान कर सकता है। विश्व प्रसिद्ध तकनीक एवं अद्वितीय शैली से बने मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों पर्यटक आएंगे। पर्यटकों के आने से शहर के धर्मशाला, होटल, रेस्टारेन्ट, परिवहन और कलाकृति प्रत्येक क्षेत्र का विकास होगा। यही नहीं आने वाले पर्यटक भी अयोध्या से लौट कर भी हमारी परम्परा व संस्कृति का गुणगान करेंगे।

प्रभु श्रीराम का जन्म अयोध्या में होना एक प्रतीक मात्र है। वह तो इस पूरी सृष्टि के आधार हैं। वह आदर्श पुरुष

ही नहीं बल्कि मर्यादाओं को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम हैं। वह एक आदर्श पुत्र और राजा भी हैं। इसलिए श्रीराम के रामराज्य को सभी लोग हर युग में आदर्श मानकर उसे स्थापित करने का प्रयास करते हैं। रामराज्य का अर्थ एक व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि एक आदर्श शासन की स्थापना है, जिसमें राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक हों। राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन करें तो समस्त प्रजा सुख की अनुभूति करते हुए अपने पिता तुल्य राजा के प्रति समर्पित एवं विश्वास से परिपूर्ण हो।

श्री राम सारे विश्व के लिए हितकारी, कल्याणकारी और लाभदायक है। भगवान वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण में भगवान रामचंद्र के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम से सुशोभित किया है क्योंकि वह सहनशीलता, धैर्य, सहयोग, प्यार, क्षमा, वीरता के गुणों से संपन्न थे।

राम पूरी मानव जाति को प्रेरणा देने वाले आदर्श हैं और वह सृष्टि के प्राण हैं। सभी मापदंडों में आदर्श स्थापित करने के कारण ही अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। भगवान राम भारतवर्ष की आत्मा हैं। उन्हें भारत से अलग नहीं रखा जा सकता। अयोध्या में श्रीराम का मंदिर बनना भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। मंदिर निर्माण हो रहा है तो धर्म की विजय पताका भी जोरों से फैल रही है। मंदिर निर्माण का उद्देश्य भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराना भी है।

अयोध्या में बना भगवान श्रीराम का मंदिर सदियों तक पूरी मानव जाति को धर्म का आचरण करने को प्रेरित करता रहेगा। मानव जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रेरणा स्त्रोत एवं आदर्श हैं। प्रभु श्रीराम लोगों के जीवन रूपी नइया को पाप रूपी अंधकार से धर्म रूपी उजाले की ओर ले जाते हैं। भगवान राम का जीवन हर युग में आदर्श एवं प्रासंगिक रहा है। उनके आदर्शों की प्रासंगिकता आज और भी अधिक बढ़ जाती है। उनके आदर्श हमारे जीवन पथ को प्रशस्त करते हैं। संसार का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका व्यवहारिक आदर्श उत्तर राम ने अपने आचरण से नहीं दिया हो। उनके जीवन में संपूर्ण संसार समाया हुआ है। वह ऐसे अवतार हैं जिन्होंने अपनी वाणी से नहीं बल्कि आचरण से जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। असाधारण होकर भी अपने साधारण जीवन से पूरे संसार का नेतृत्व किया। भगवान राम भारतीय संस्कृति के ऐसे नायक है जिन्होंने समाज के सुख-दुख और उसकी रचना को बहुत नजदीक से देखा और समझा है। अयोध्या के राजकुमार और राजा से भी अधिक बड़ी भूमिका इस जननायक में दिखाई देती है। भगवान राम ने राष्ट्र के सोए हुए भाग्य को जगाने का काम किया।

श्री राम चंद्र जी ने अपने शासनकाल में लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया करने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जिसे सदियों से राम राज्य कहा गया है, जहां किसी भी तरह का भेदभाव और शोषण नहीं होता था। इसलिए समस्त भारत में बरसों से लोग राम लीलाएं बड़ी खुशी और श्रद्धा से करते आए हैं। प्रभु श्रीराम का आज्ञाकारी पुत्र के रूप में होना, भाइयों का आपसी प्यार, पत्नी का पति के प्रति पूर्ण समर्पण तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण का संदेश वर्तमान युग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

'राम' एक आदर्श पुरुष रूप में जन-जन में समाए हुए हैं। यही नहीं प्रभु श्रीराम हमारी सोच में बसे हुए हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में किसी भी चीज का मोह नहीं रखा और त्याग को सर्वोपरि माना। भगवान राम ने राजपाट का ही नहीं, अपनी पत्नी प्रिय सीता का 'लोक-संग्रह' के लिए त्याग कर दिया। राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध परम्परा का प्रतीक है। राम की सुंदर छवि के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है।

उम्मीद से पांच गुना ज्यादा आई भीड़, संभालने के लिए ट्रस्ट ने किया बड़ा फैसला

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार, उन लोगों का अनुमान था कि मंदिर बनने के बाद एक से डेढ़ लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन पांच लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। भक्तों की इतनी भीड़ से पूरी व्यवस्था चरमरा गई...

अयोध्या में आ रही राम भक्तों की भारी भीड़ से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। होटल, पांडाल, धर्मशाला हो या आश्रम, पूरी तरह भर गए हैं। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी कहीं पैर रखने भर की जगह नहीं बची है। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे हड़बड़ी में तुरंत दर्शन के लिए न आएं, बल्कि वे बाद में दर्शन के लिए पहुंचें, जिससे व्यवस्था बनाने में सहूलियत हो। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने के लिए अभी तक एक द्वार पुरुषों के लिए और एक द्वार महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसे बढ़ाकर अब तीन द्वार पुरुषों के लिए और तीन द्वार महिलाओं के लिए कर दिया गया है। अनुमान है कि इससे अब तक अयोध्या पहुंच चुके सभी भक्तों को दर्शन मिल जाएगा। इसके बाद आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था बनाने में सुविधा हो जाएगी।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार, उन लोगों का अनुमान था कि मंदिर बनने के बाद एक से डेढ़ लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन पांच लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। भक्तों की इतनी भीड़ से पूरी व्यवस्था चरमरा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद करने का आदेश दिया और भीड़ संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था की। अयोध्या आने वाली बसों और ट्रेनों को भी सीमित करना पड़ा है। योगी की अपील के बाद ही भक्तों की संख्या पर नियंत्रण लगाना संभव हो सका।

अयोध्या के स्थानीय प्रशासन को भी इतनी भारी भीड़ को संभालने का कोई अनुभव नहीं था, लिहाजा स्थिति गड़बड़ हो गई। मूलभूत सुविधाओं की भी कमी हर जगह महसूस की गई। हालांकि, प्रशासन का अनुमान है कि अब आने वाले समय में भीड़ को नियंत्रित करना संभव हो सकेगा।

भाजपा की भी बड़ी संख्या में पूरे देश से भक्तों को राम मंदिर लाकर भगवान का दर्शन कराने की योजना है। इसे 23 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया है, जो 25 मार्च तक चलेगा। लेकिन अयोध्या के हालात को देखते हुए रामलला के दर्शन के लिए ले जाने वाली संख्या में कुछ कमी की जा सकती है।

राम नवमी को स्थिति संभालने की चिंता

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अभी से इस बात की चिंता है कि यदि अभी से भक्तों की इतनी बड़ी संख्या दर्शन के लिए अयोध्या आ रही है, तो रामनवमी के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस भीड़ को संभालना ट्रस्ट और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार, मंदिर और स्थानीय प्रशासन पहले से ही भक्तों की संख्या का अनुमान कर व्यवस्था करने की तैयारी करेगा।

15 किलो सोना, 18,000 पन्ने और हीरों से सजे हैं भगवान रामलला के आभूषण

गुजरात में तैयार हुआ है रत्नजड़ित स्वर्ण मुकुट

अध्यात्म रामायण, श्रीमद वाल्मिकी रामायण, श्री रामचरितमानस और आलवंदर स्तोत्र जैसे पवित्र ग्रंथों द्वारा निर्देशित कारीगरों ने में वर्णित शास्त्रीय सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक चीज का सावधानीपूर्वक निर्माण किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच की राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में पांच साल के बच्चे के रूप में भगवान राम का चित्रण उत्तम आभूषणों से सुसज्जित है जो उनके दिव्य कद का प्रतीक है। अध्यात्म रामायण, श्रीमद वाल्मिकी रामायण, श्री रामचरितमानस और आलवंदर स्तोत्र जैसे पवित्र ग्रंथों द्वारा निर्देशित कारीगरों ने में वर्णित शास्त्रीय सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक चीज का सावधानीपूर्वक निर्माण किया। इस शानदार आभूषण में 14 गहने शामिल हैं, जिनमें एक तिलक, एक मुकुट, चार हार, एक कमरबंद, दो जोड़ी पायल, विजय माला और दो अंगूठियां शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, कम से कम 15 किलो सोने से तैयार और 18,000 हीरे और पन्ने से सजे ये आभूषण मात्र 12 दिनों में बनकर तैयार हो गए थे। रामलला के लिए आभूषण तैयार करने की जिम्मेदारी लखनऊ के हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स को सौंपी गई थी, जिनसे करीब 15 दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने संपर्क किया था।

माथे पर लगा तिलक 16 ग्राम सोने से तैयार किया गया था, जिसके बीच में तीन कैरेट के हीरे और दोनों तरफ 10 कैरेट के हीरे जड़े हुए थे। बर्मी माणिक ने इसका आकर्षण और बढ़ा दिया। 65 ग्राम वजनी एक पन्ना अंगूठी ने पहनावे को पूरा किया, जो भगवान राम के ज्ञान और उनके वन-निवास के दिनों के दौरान प्रकृति के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक था, जिसमें केंद्र में चार कैरेट हीरे, 33 कैरेट पन्ना और एक जाम्बियन पन्ना शामिल था।

वहीं, रामलला के विग्रह पर सुशोभित बहुमूल्य रत्नजड़ित स्वर्ण मुकुट और मंदिर की चांदी की दो प्रतिकृति गुजरात के सूरत में तैयार की गईं। प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में सोमवार को जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई तब रामलला के सिर पर वह मुकुट उनकी शोभा बढ़ा रहा था। सूरत स्थित उद्योगपति और ग्रीनलैब डायमंड्स के प्रमुख मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपये का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया, जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है और इसका वजन छह किलोग्राम है। सूरत के डी खुशालदास ज्वैलर्स के मालिक दीपक चोकसी ने बताया कि तीन किलोग्राम वजनी मंदिर की चांदी की प्रतिकृतियां उनके प्रतिष्ठान ने लगभग चार महीने पहले बनाई गई थीं, जब राम मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा की गई थी।

अयोध्या बनेगा देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र

हर साल आएंगे 5 करोड़ लोग, जेफरीज की रिपोर्ट में खुलासा

जेफरीज के मुताबिक, धार्मिक पर्यटन अब भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा खंड है। कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र बुनियादी ढांचे की बाधाओं के बावजूद हर साल एक-तीन करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शहर में हर साल कम-से-कम पांच करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। यह संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं अधिक है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि हवाईअड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से यूपी का यह शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नए हवाईअड्डे, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सुविधाओं के लिए अयोध्य पर 10 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए गए हैं। इससे शहर में नए होटल खुलेंगे और अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होगा। जेफरीज के मुताबिक, धार्मिक पर्यटन अब भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा खंड है। कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र बुनियादी ढांचे की बाधाओं के बावजूद हर साल एक-तीन करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसलिए, बेहतर संपर्क व बुनियादी ढांचे के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र (अयोध्या) का निर्माण बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है।

जीडीपी में 443 अरब डॉलर का होगा योगदान : रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटन ने कोविड पूर्व यानी 2018-19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032-33 तक इसके 8 फीसदी की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।

इनसे आगे निकल जाएगी अयोध्या

- अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हर साल 3-3.5 करोड़ लोग आते हैं।
- तिरुपति मंदिर में 2.5-3 करोड़ पर्यटक आते हैं।
- वेटिकन सिटी में हर साल करीब 90 लाख पर्यटक आते हैं।
- सऊदी अरब के मक्का में सालाना करीब दो करोड़ पर्यटक आते हैं।
- अयोध्या में हर साल 5 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आने की संभावना।

इसलिए बढ़ेंगे पर्यटक

रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या में नए हवाईअड्डे का पहला चरण शुरू हो गया है। यह 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है। वर्तमान में अयोध्या में 590 कमरों वाले करीब 17 होटल हैं। 73 नए होटल तैयार किए जा रहे हैं। इंडियन होटल्स, मैरियट और विंडहैम पहले ही होटल बनाने के लिए समझौते कर चुके हैं। इसके अलावा, आईटीसी भी अयोध्या में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। ओयो की योजना अयोध्या में 1,000 कमरे जोड़ने की है। 1,200 एकड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की योजना।

भक्तों का सैलाब, सभी को हो दर्शन तो नियमों में हुआ ये बदलाव

दर्शन के पहले दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस दिन मंदिर में पांच लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। हालांकि भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहाँ काफी अव्यवस्था भी फैल गई। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी की सुरक्षा की सभी इंतजाम पस्त पड़ गए। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन में भक्तों का सैलाब उमड रहा है। लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं ताकि रामलला के दर्शन कर सके। अयोध्या में। 30 जनवरी से आम जनता के लिए रामलला के दर्शन खुले है। इसके बाद से ही लगातार मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन के पहले दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस दिन मंदिर में पांच लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। हालांकि भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहाँ काफी अव्यवस्था भी फैल गई। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी की सुरक्षा की सभी इंतजाम पस्त पड़ गए। सुरक्षा बलों के लिए भी भक्तों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। इस भीड़ को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर का जायजा लिया है। उन्होंने सुरक्षा नियमों और मंदिर में भीड़ संभालने के नियम में बदलाव किया है। अयोध्या में रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि भक्तों की भीड़ लगातार मंदिर आ रही है। भीड़ को संभालने के लिए हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। लोग लाइन में आएंगे और उन्हें लाइन में ही दर्शन कराए जाएंगे। वर्तमान में भीड़ को देखते हुए हमारी अपील है कि सिर्फ युवा और स्वस्थ लोग ही रामलला के दर्शन करने आए। बुजुर्ग, बच्चे और अस्वस्थ लोग दो सप्ताह बाद मंदिर में दर्शन करने की योजना बनाए। मंदिर में भीड़ को देखते हुए खास चैनल बनाए गए हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया का सके।

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद

सरकार दे सकती है कोरोनाकाल में रोके गए 18 माह के डीए का एरियर

केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था...

केंद्र सरकार में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसी उम्मीद है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते 'डीए' का एरियर जारी हो जाएगा। हालांकि सरकार इस बाबत, कई बार कह चुकी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य, मुकेश सिंह ने 20 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह भुगतान अविलंब जारी किया जाए। तब केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का हवाला दिया था। उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अगर सरकार, रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर जारी करती है, तो सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। इससे कर्मियों और पेंशनरों का वह भरोसा प्रबल होगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, सरकार ने उसे मान्यता दी है। उनकी लगन का सम्मान किया है।

बकाया राशि जारी न होने से चिंतित : भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने अपने पत्र में कहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) की बकाया राशि जारी न होने से चिंतित हैं। कर्मचारी, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझते हैं। उसके चलते ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तें रोक दी गईं थीं। हालांकि उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोरोनाकाल के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपना योगदान दिया था। उनके अटूट समर्पण भाव और कड़ी मेहनत के चलते देश में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित हो सकी थीं। सरकार को अब 18 माह के डीए का एरियर जारी करना चाहिए। वह राशि, जिसे अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोका गया था, अब उसे योग्य लाभार्थियों को वितरित किया जा सकता है। सरकार का यह भाव, निस्संदेह कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा।

वित्त मंत्रालय को पहले भी दिया है प्रतिवेदन : डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। 'नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है।

केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स, कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गत वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाए साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब, केंद्र सरकार

अपने कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ से अधिक की डीए/डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए/डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। सी. श्रीकुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को छह फीसदी ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है।

कोरोनाकाल में रोका गया था डीए का भुगतानः केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। पिछले साल के बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सी. श्रीकुमार के मुताबिक, सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था।

सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोनाकाल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11 फीसदी वृद्धि हो गई, जबकि डेढ़ साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थीं। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया तीन किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई।

राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ थाः एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्रीकुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव/कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/04/2021 के माध्यम से डीए/डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए/डीआर की तीन किस्तों का भुगतान 01/01/2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैद्य अधिकार है। इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए।

फरवरी से सभी 11 लोस सीटों पर BJP शुरू करेगी चुनावी कार्यालय...

छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने तय किया है कि 31 जनवरी तक सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोल लिए जाएं। चुनाव के लिए तीन तरह की प्रबंधन समितियां बनाने का भी निर्णय लिया गया है। अगले कुछ दिनों में इस समितियों के संयोजकों के नाम भी घोषित हो जाएंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के चलते तीन तरह के प्रवास की योजना बनाई गई है। इसमें पहला क्लस्टर प्रवास, दूसरा लोकसभा औऱ तीसरा विधानसभा प्रवास शामिल है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजनांदगांव आ रहे हैं। पार्टी का हर बड़ा पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री प्रवास के दौरान दो बड़ी बैठक और एक सभा या एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा।

क्लस्टर प्रवास में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, गृहमंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह औऱ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक क्लस्टर में आएंगे। वे इस दौरान लोकसभा की प्रबंधन समिति, प्रबुद्ध जन से मुलाकात के अलावा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और एक बड़ी सभा मे शामिल होंगे। लोकसभा प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी या नेता एक से दो दिन के लिए आएंगे। वे भी लोकसभा की प्रबंधन समिति की बैठक के अलावा पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विधानसभा के प्रवास के दौरान राज्य के बड़े नेता, संगठन के बड़े नेता और राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ विधायक राज्यों की विभिन्न विधानसभाओ में जाकर प्रवास करेंगे। वे विधानसभा स्तर पर बनी समितियो की बैठक में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों की बैठक के अलावा स्थानीय कार्यकर्ताओ की बैठक में शामिल होंगे।

क्लस्टर के पार्टी ने बनाए तीन प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा की 11 सीटों को तीन कलस्टर में बांटा गया है। इसके तीन प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को बस्तर, महासमुंद, कांकेर औऱ राजेश मूणत को रायपुर, दुर्ग ,राजनांदगांव, जांजगीर चांपा की जबकि अमर अग्रवाल को बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है । प्रभारी के अलावा सह प्रभारी, संयोजक और सहसंयोजक भी बनाए गए हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर ने कोर ग्रुप के सदस्यों प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और क्लस्टर प्रभारी से चर्चा कर लोकसभा के लिए जीतने योग्य प्रत्याशियों की जानकारी ली थी। इसमें प्रभावी रूप से जनता के बीच में कैसे जाएं उस पर विशेष चर्चा की गई है। सभी लोकसभा सीटों की विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में लोकसभा की सभी विधानसभा की प्रबंध समितियां बनाई जाएंगी। प्रबंध समिति की बैठक लेने राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गईं विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से भी चर्चा की है।

कर्ज के जाल में फंसी हुई है मध्यप्रदेश की सरकार... ?

370 योजनाओं पर लटकी तलवार

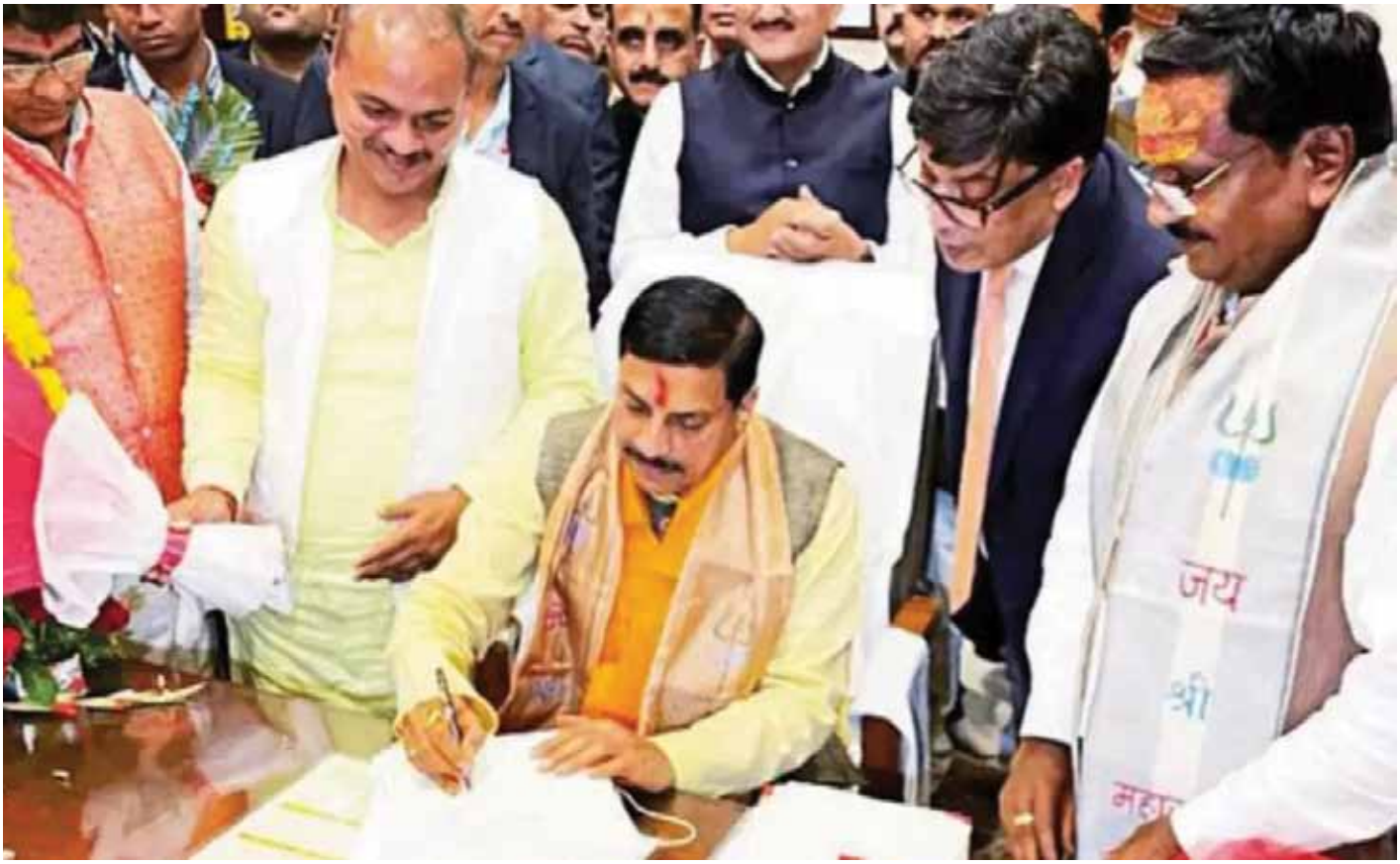

पिछले 10 महीनों (31 मार्च, 30 जून और 8 दिसंबर) में तीन सरकारी आदेश जारी किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना योजनाओं के लिए धन नहीं निकाला जाना चाहिए। कोई भी विभाग अछूता नहीं रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 22 योजनाएँ और मद हैं, जिनकी राशि ठंडे बस्ते में है।

नकदी संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 370 योजनाएं रोक दी हैं, जिनमें स्कूल, आईटी उद्योग, कृषि ऋण, मेट्रो रेल और यहां तक कि प्रधानमंत्री सड़क योजना भी शामिल है। आधिकारिक तौर पर रुख यह है कि कोई भी परियोजना बंद नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा ताले में बंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 महीनों (31 मार्च, 30 जून और 8 दिसंबर) में तीन सरकारी आदेश जारी किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना योजनाओं के लिए धन नहीं निकाला जाना चाहिए। कोई भी विभाग अछूता नहीं रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 22 योजनाएँ और मद हैं, जिनकी राशि ठंडे बस्ते में है। नई भाजपा सरकार को वित्त प्रबंधन में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। उसे विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला और एक महीने से भी कम समय में उसने 2,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है।

टीओआई के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दूसरे लोन के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। राज्य पर राजकोषीय दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी तब खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार की चुनाव पूर्व घोषणाओं और योजनाओं से खर्च में कम से कम 10% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। असर साफ़ दिख रहा था। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी जीत मिलने के ठीक पांच दिन बाद, और भी योजनाएं रोक दी गईं। इनमें तीर्थ यात्रा, खेलो इंडिया एमपी, एक जिला एक उत्पाद योजना प्रबंधन, कृषि ऋण निपटान योजना, मेट्रो रेल, मॉडल स्कूलों की स्थापना, मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप, टंट्या भील मंदिर, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना, कॉलेज पुस्तकालयों का विकास, स्थापना शामिल हैं।

पिछले साल जुलाई में विधानसभा में पारित 26,816.6 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट में सरकार द्वारा लिए गए नए बाजार ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए 762 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे। अगले माह लेखानुदान से पहले विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया जायेगा। वित्त विभाग के अधिकारी यह बताने में विफल रहे कि सभी विभागों को 370 योजनाओं के लिए धन निकालने से पहले इसकी मंजूरी या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के लिए क्यों कहा गया है। एक अधिकारी ने कहा, ''धन का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। धन निकासी से पहले वित्त की अनुमति लेने का मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है। लेकिन, हाँ, सवार के कारण इसे रोक दिया जाता है। साथ ही, यह कई विभागों को योजनाओं के लिए धन के लिए वित्त विभाग से संपर्क करने से हतोत्साहित करेगा।

हर साल खर्च होते हैं 200 करोड़..

इसलिए... स्वच्छता में नंबर वन रहता है इन्दौर शहर..

इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क और जुर्माने की वसूली के साथ ही अन्य स्रोतों से इतनी ही राशि सरकारी खजाने में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वच्छता के इस मॉडल को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

इंदौर। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार सातवीं बार अव्वल रहे मध्यप्रदेश के इंदौर में शहरी निकाय की ओर से कचरा प्रबंधन पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। निगम के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क और जुर्माने की वसूली के साथ ही अन्य स्रोतों से इतनी ही राशि सरकारी खजाने में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वच्छता के इस मॉडल को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

''वेस्ट टू वेल्थ'' की थीम पर केंद्रित वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग-अलग श्रेणियों में देश के 4,400 से ज्यादा शहरों के बीच कड़ी टक्कर थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को सूरत के साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अधिकारी ने बताया, हम शहर में अपशिष्ट प्रबंधन पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम कचरे से कमाई की अलग-अलग मदों में इतनी ही रकम सरकारी खजाने में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि बायो-सीएनजी संयंत्र ''गोबर-धन'' को गीला कचरा मुहैया कराने के बदले एक निजी कंपनी की ओर से आईएमसी को हर साल 2.52 करोड़ रुपये की रॉयल्टी दी जाती है।

इसके अलावा, निजी कम्पनी शहरी निकाय को प्रचलित बाजार दर से पांच रुपये प्रति किलोग्राम कम दाम पर यह हरित ईंधन बेचती है जिससे सरकारी खजाने को लाभ होता है। उन्होंने बताया कि शहर के एक अन्य प्रसंस्करण संयंत्र को सूखा कचरा मुहैया कराने के बदले आईएमसी को एक निजी कंपनी की ओर से हर साल 1.43 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलती है। अधिकारी ने बताया कि गीले और सूखे कचरे के प्रसंस्करण के दोनों संयंत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट बेचने से आईएमसी को नौ करोड़ रुपये की सालाना आय होती है। अधिकारी ने बताया कि आईएमसी ने एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने के बाद इसके पुनर्चक्रण के जरिये विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के क्रेडिट भी हासिल किए हैं।

बहरहाल, शहर के लगातार विस्तार के मद्देनजर आईएमसी के सामने स्थानीय लोगों से कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। आईएमसी अधिकारी का दावा है कि कचरा संग्रहण के बदले शहर के कुल 6.5 लाख घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थानों से नियमित शुल्क वसूला जा रहा है। इसके अलावा, गंदगी फैलाने पर संबंधित लोगों से जुर्माना भी वसूला जाता है। अधिकारी ने बताया कि शहर में औसत आधार पर हर दिन 692 टन गीला कचरा, 683 टन सूखा कचरा और 179 टन प्लास्टिक अपशिष्ट अलग-अलग श्रेणियों में इकट्ठा किया जाता है। कचरा संग्रहण के लिए शहर भर में करीब 850 गाड़ियां चलती हैं।

रामजानकी राजेश पण्डा
अध्यक्ष नगर परिषद पीछोर

इरफान खान, उपाध्यक्ष
नगर परिषद पीछोर

पीयूष श्रीवास्तव, मुख्य
नपा अधिकारी, पीछोर

सभी पिछोर नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपील

1. निकाय द्वारा जारी कंप्यूटरीकृत संपत्ति कर जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
2. जल ही जीवन है जल का दुरुपयोग ना करें।
3. भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
4. नगर पालिका की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करें।
5. नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें कचरा नियत स्थानों पर ही डालें।
6. जन्म मृत्यु का पंजीयन समय पर कराएं तथा निकाय से कंप्यूटरीकृत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
7. नगर पालिका से अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें।
8. शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।
9. नगर में वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करें।

बिलौआ नगर परिषद की ओर से सभी नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एव अपील

1.स्वच्छता बनाये रखे, 2.जल, मकान, टेक्स समय पर जमा कराए 3. कचरा कचरा गाड़ी मैं ही डाले...

श्रीमती विजयलक्ष्मी चौरसिया
अध्यक्ष : नप बिलौआ

अनीता राम अवतार रावत
उपाध्यक्ष, बिलौआ

सुनील चौरसिया
पार्षद बिलौआ

पीयूष श्रीवास्तव
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

अपीलकर्ता : नगरपालिका

भारत ने वैश्विक भलाई और लैंगिक समानता के लिए नए गठबंधन की घोषणा की

डब्ल्यूईएफ प्रमुख भी रहे मौजूद

महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस गठबंधन का विचार जी-20 नेताओं के घोषणापत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से आया है। ईरानी ने डब्ल्यूईएफ को भारत का बहुत मजबूत समर्थन करने के लिए भी बधाई दी।

भारत ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से इतर गुरुवार को दावोस में वैश्विक भलाई, लैंगिग समानता और आर्थिक समानता के लिए एक नए गठबंधन की घोषणा की। इस दौरान विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और चेयरमैन क्लॉस श्वाब भी मौजूद थे। उन्होंने इस पहल का समर्थन करने की भी बात कही है। उद्योग मंडल सीआईआई की ओर से आयोजित डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक से इतर आयोजित स्वागत समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी व अन्य ने भी शिरकत की।

महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस गठबंधन का विचार जी-20 नेताओं के घोषणापत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से आया है। ईरानी ने डब्ल्यूईएफ को भारत का बहुत मजबूत समर्थन करने के लिए भी बधाई दी।

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल उच्च विकास दर दी है और महंगाई को नियंत्रित किया है, बल्कि 80 करोड़ भारतीय नागरिकों की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इसका विदेशों में भी लोगों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'यह गठबंधन वैश्विक भलाई के लिए है जैसा कि नाम से पता चलता है।'

ईरानी ने देश में सामाजिक क्रांति लाने, महिलाओं को सुशासन के केंद्र में रखने के लिए प्रधानमंत्री के एजेंडे की भी सराहना की। मंत्री पुरी ने कहा कि भारत का डब्ल्यूईएफ के साथ हमेशा से विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि भारत महिला केंद्रित विकास से महिला नीत विकास की ओर बढ़ गया है।

डब्ल्यूईएफ प्रमुख श्वाब ने कहा कि जलवायु, संघर्ष और एआई के अलावा दावोस में चर्चा के मुख्य विषयों में से एक भारत भी है। उन्होंने कहा, 'हम न केवल भारत की पहल से गठबंधन का समर्थन करेंगे बल्कि इसका एक मजबूत भागीदार बनेंगे।' उन्होंने चुनावी साल में इतना मजबूत प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए भी भारत को धन्यवाद दिया। वैश्विक भलाई के लिए बने इस गठबंधन को मास्टरकार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, बायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवार्तिस, आईएमडी लॉसेन और सीआईआई के माध्यम से उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारों से समर्थन मिला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस गठबंधन को सीआईआई सेंटर फॉर वुमन लीडरशिप की ओर से संचालित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत भागीदार के रूप में इस अभियान को समर्थन देंगे।

कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को किया अलर्ट

गूगल में एक बार फिर हो सकती है कर्मियों की छंटनी

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने बड़ा एलान किया है। गूगल के सीईओ ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आप इस साल और अधिक छंटनी के लिए तैयार रहें। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब गूगल अपने कर्मियों को निकालने के लिए कह रहा है। कंपनी पहले भी कई बार अपने कर्मियों को निकाल चुका है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के एक आंतरिक मेल में कहा गया है कि गूगल विभिन्न विभागों में अभी हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है। मेल के माध्यम से पिचाई ने कर्मचारियों से कहा कि कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, जिनके लिए इस प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश किया जाएगा। निवेश की यह क्षमता हासिल करने के लिए कंपनी को कठोर विकल्प चुनने होंगे। हालांकि, पिचाई का कहना है कि यह कटौती हर टीम को प्रभावित नहीं करेगी। पिचाई ने कहा कि वे जानते हैं कि कुछ सहकर्मियों और टीमों पर इसका असर देखना सबके लिए मुश्किल होगा। लेकिन, छंटनी को सरल बनाने और कुछ क्षेत्रों में गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भार घटाना ही होगा। इनमें से कई बदलावों की घोषणा की जा चुकी है।

पिछली जनवरी में ही 12 हजार कर्मचारियों की हो गई थी छुट्टी

इससे पहले सितंबर 2023 में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने कर्मचारियों की छंटनी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया था। पिछले साल भी जनवरी में ही अल्फाबेट ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। इस फैसले के कारण अल्फाबेट के कर्मिचारियों के आकंड़ों में छह प्रतिशत की गिरवाट दर्ज की गई थी। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट की मानें तो गूगल 2024 की शुरुआत में ही करीब 1000 लोगों को बर्खास्त कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अब इन कर्मचारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करेगी।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी पटेल ने किया निविन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा शौचालय का भूमिपूजन

चलित रसोई घर को हरी झंडी दिखाकर की शुरूआत, 5 रुपए में मिलेगा मिलेगा भोजन

शाम 07 बजे बस स्टैंड स्थित नगर निगम की भूमि पर शॉपिंग कंपलेक्स एवं तिलक वार्ड मे गणेश विधालय के पास शौचालय निर्माण का भूमि पूजन माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस महापौर माधुरी अतुल के आतिथ्य में हुआ माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि , देश के प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। खुले में शौच न हो इस लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत ही बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य की लागत 89.94 लाख की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं शौचालय निर्माण कार्य की शुरूआत भूमि पूजन के साथ की गयी। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत वार्ड 7 तिलक वार्ड में गणेश स्कूल के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य की लागत 19.60 लाख की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा इसके पश्चात माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस महापौर माधुरी अतुल पूर्व महापौर अतुल पटेल ने आज चलित रसोई घर जिसमे कोई भी व्यक्ति को 5 रु में भरपेट भोजन मिलेगा माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई केंद्रों (Deendayal Rasoi) का संचालन किया जा रहा है, जहां पर गरीबों को 5 रुपए में भोजन की थाली दी जाती है। इसी केंद्र को अब अडपेट किया गया है। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि चलित रसोई घर में गरीब लोगो के साथ आम लोगो को भी 5 रुपए में भोजन मिलेगा व्यक्ति जहा रहेगा यह रसोई घर तुरंत पहुंच जायेगा इसी के तहत आज मंगलवार को नगर पालिक निगम में द्वारा संचालित चलित रसोई केंद्रों' को हरी झंडी दिखाई है।आपको बता दें की अन्य नगरीय निकाय में एक-एक चलित रसोई केन्द्र शुरू किये जायेगे ।नगर निगम महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि 5 रुपए में भोजन देने की बात आम नागरिकों के पेट में नहीं पचती। आखिर कोई कैसे इतने सस्ते में भोजन दे सकता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार रसोई केंद्रों में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल एक रुपए प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराती है।

यह अनाज उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद रसोई संचालक भोजन 5 रुपए में देते हैं।इस अवसर पर खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस (दीदी), नगर निगम महापौर माधुरी अतुल पटेल,निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव , पूर्व महापौर अतुल पटेल जी, जिला अध्यक्ष श्री मनोज लधवे जी, MIC सदस्य संभाजी सगरे , संध्या शिवहरे नितेश रोशन दलाल धनराज महाजन राकेश खत्री , गौरव शुक्ला राजेश महाजन ,अशोक महाजन स्वाति हेमंत महाजन ,भारत भुजडे , विनोद पाटिल एवं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू,अशोक पाटील, गोपाल महाजन जन संपर्क आधिकारी हरीश मोरे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आदी उपस्थित थे।

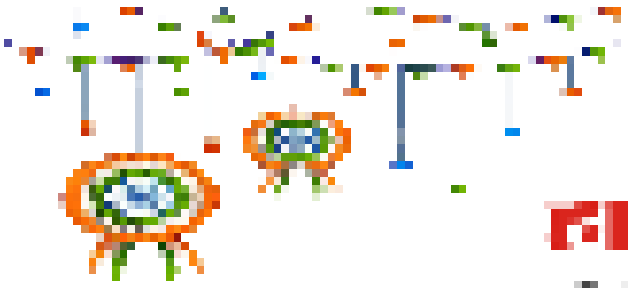

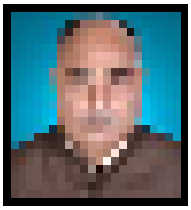

देशवासियों को
गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
प्रदीप भदौरिया
कार्यालय नगर पालिका परिषद, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

जोधपुर मिष्ठान्न भंडार डबरा की ओर से
समस्त डबरा वासियों को गणतंत्र दिवस
बहुत बहुत शुभकामनाएं
26 जनवरी
गणतंत्र दिवस
हमारे यहाँ शुद्ध एवं ताजी मिठाईयां
सदैव उपलब्ध रहती है
शुभकामनाएं कर्ता : प्रो. महेंद्र एवं समस्त परिवार

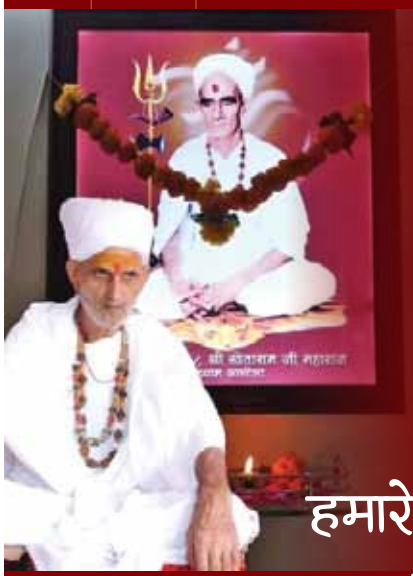

2028 में उज्जैन कुंभ मेले में ₹12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद :सरकार

कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यादव ने अधिकारियों को क्षिप्रा नदी में अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोसी शहर इंदौर और देवास में विभिन्न स्थानों पर छोटे बांध बनाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है, जिसके मद्देनजर क्षिप्रा नदी की सफाई और अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए 'स्टॉप डैम' (छोटे बांध) के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उज्जैन में रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मेला आयोजन के मद्देनजर निर्देश दिए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, ऐसा अनुमान है कि लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु वर्ष 2028 कुंभ मेले में हिस्सा लेंगे।

कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यादव ने अधिकारियों को क्षिप्रा नदी में अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोसी शहर इंदौर और देवास में विभिन्न स्थानों पर छोटे बांध बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए और इसका पानी 2028 से पहले पीने योग्य हो जाए।

सिंहस्थ से पहले संवारे जाएंगे इंदौर जिले के पर्यटन स्थल, सिक्स लेन बनेगी इंदौर-उज्जैन सड़क...

सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इंदौर जिले में होने वाले विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों ने प्रस्ताव तैयार किए है। इन प्रस्तावों की समीक्षा शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा की गई। मप्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंदौर-उज्जैन सड़क को सिक्स लेन बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन आसान हो सके। इसके अतिरिक्त जिले के पर्यटन स्थलों को भी संवारा जाएगा।

इंदौर जिले में सिंहस्थ-2028 से पहले कई विकास कार्य किए जाना हैं। प्रशासनिक संकुल में शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने सिंहस्थ-2028 के लिए विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की समीक्षा की। मुख्य रूप से मंदिरों एवं स्मारकों के नवीनीकरण, शिप्रा शुद्धीकरण, मेला क्षेत्र विकास, सड़कें और पुल-पुलियाओं का नवनिर्माण, सड़क चौड़ीकरण, नदी व जल निकायों का विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, पावर स्टेशन

और विद्युत लाइन, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी विकास, सुंदरीकरण, फायर स्टेशन आदि के संबंध में विभागों द्वारा तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर निगम, पुलिस विभाग, मप्र औद्योगिक विकास निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। बैठक में निगमायुक्त हर्षिका सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार, अपर कलेक्टर रोशन राय और निशा डामोर सहित विकास कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

साख व्यवसाय में कार्यरत

दि स्टेट सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा

हमारी संचालित जमा योजनाएं

- बचत अमानत खाता
- दैनिक अमानत खाता
- सावधि बचत अमानत खाता
- अनिवार्य अमानत खाता
- आवर्ती अमानत खाता
- अल्पावधि अमानत खाता
- मासिक आय योजना

राधेश्याम गुप्ता डायरेक्टर

आज ही संस्था में सदस्य बनकर जमा एवं ऋण योजनाओं का लाभ उठाएं।

रोहिरा कॉम्प्लेक्स, संत कंवर राम चौराहा, ठाकुर बाबा रोड, डबरा

हमारी संचालित ऋण योजनाएं

- प्राथमिक ऋण
- वाहन ऋण
- दो पहिया वाहन ऋण
- उपभोक्ता ऋण
- स्वर्ण आभूषण ऋण
- दैनिक जमा ऋण
- सावधि ऋण

पंकज जैन डायरेक्टर

समस्त क्षेत्रावासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं

शुभ दिवाली

आनंद कुमार
एसआई एवं ठाठीपुर थाना प्रभारी

समस्त क्षेत्रावासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं

शुभ दिवाली

शुभकामनाएं कर्ता : प्रो. नारायण दास गुप्ता
पूर्व पार्षद एवं चेयरमैन नगर पालिका
डबरा, पूर्व लॉयन्स क्लब अध्यक्ष

हिन्दी है राष्ट्रीयता की प्रतीक

फिर उपेक्षा क्यों?

हिंदी इस समय विश्व में तेजी से उभरती हुई भाषा है। दुनियाभर में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यही वजह है कि अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनियाभर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।

विश्व हिन्दी दिवस मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में फैले हिंदी जानकारों को एकजुट करना, हिन्दी को विश्व स्तर पर स्थापित एवं प्रोत्साहित करना और हिंदी की आवश्यकता से अवगत कराना है। अंग्रेजी भाषा भले ही दुनियाभर के कई देशों में बोली है और लिखी जाती है. लेकिन हिंदी हृदय की भाषा है। विश्व योग दिवस, विश्व अहिंसा दिवस आदि भारतीय अस्मिता एवं अस्तित्व से जुड़े विश्व दिवसों की श्रृंखला में विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ताकि विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा हो तथा हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिले। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी, 2006 को मनाया गया था। आज हिन्दी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली तीसरी भाषा है, विश्व में हिन्दी की प्रतिष्ठा एवं प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में उसकी उपेक्षा एक बड़ा प्रश्न है। सच्चाई तो यह है कि देश में हिंदी अपने उचित सम्मान को लेकर जूझ रही है। राजनीति की दूषित एवं संकीर्ण सोच का परिणाम है कि हिन्दी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान आजादी के अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र में अंग्रेजी को मिल रहा है। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरूर ली जाए लेकिन तकनीकी एवं कानून की पढ़ाई एवं राजकाज की भाषा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज भी भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी में ही कामकाज होना राष्ट्रीयता को कमजोर कर रहा है। हिन्दी के बहुआयामी एवं बहुतायत उपयोग में ही राष्ट्रीयता की मजबूती है, जीवन है, प्रगति है और शक्ति है किन्तु इसकी उपेक्षा में विनाश है, अगति है और स्खलन है।

हिंदी इस समय विश्व में तेजी से उभरती हुई भाषा है। दुनियाभर में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यही वजह है कि अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनियाभर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और नेपाल आदि में लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन में उस दौरान 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बाद में साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे डॉ.मनमोहन सिंह ने हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने के मकसद से भी मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में स्थित भारत के सभी दूतावासों में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एथनोलॉग के वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण में बताया गया है कि दुनियाभर की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, इनमें हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गयी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेट हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है, हिन्दी राष्ट्रीयता की प्रतीक भाषा है, उसको राजभाषा बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठापित करने के नाम पर भारत में उदासीनता एवं उपेक्षा की स्थितियां परेशान करने वाली है, विडम्बनापूर्ण है। विश्वस्तर पर प्रतिष्ठा पा रही हिंदी को देश में दबाने की नहीं, ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हमने जिस त्वरता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में पहल की, उसी त्वरा से राजनैतिक कारणों से हिन्दी की उपेक्षा भी है, यही कारण है कि आज भी देश में हिन्दी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। देश-विदेश में इसे जानने-समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के प्रयत्नों को राष्ट्र सदा स्मरणीय रखेगा। क्योंकि मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर न केवल हिन्दी को गौरवान्वित किया बल्कि देश के हर नागरिक का सीना चौड़ा किया। हिन्दी का हर दृष्टि से इतना महत्व होते हुए भी भारत में प्रत्येक स्तर पर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों? दुनिया में हिन्दी का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होना, इन्हीं विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण परिस्थितियों को ही दर्शाता है। स्वभाषा हिन्दी, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय प्रतीकों की उपेक्षा एक ऐसा प्रदूषण है, एक ऐसा अंधेरा है जिससे ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की भी प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ही हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विशेषतः अदालतों में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम रहना, एक बड़ा प्रश्न है। देश की सभी निचली अदालतों में संपूर्ण कामकाज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होता है, किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यही काम केवल अंग्रेजी में होता है। यहां तक कि जो न्यायाधीश हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं जानते हैं वे भी अपीलीय मामलों की सुनवाई में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं। आमजन के लिए न्याय की भाषा कौन-सी हो, इसका सबक भारत और भारतीय न्यायालयों को अबू धाबी से लेने की जरूरत है। संयुक्त अरब अमारात याने दुबई और अबूधाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। वहां के जनजीवन में हिन्दी का सर्वाधिक प्रचलन है। दुनिया में जितने भी देश महाशक्ति के दर्जे में आते हैं, उनकी शासकीय कार्य एवं अदालतों में मातृभाषा चलती है। यूरोपीय देशों में जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ी, वैसे-वैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रखर होता चला गया। रूस, चीन, जापान, वियतनाम और क्यूबा में भी मातृभाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन भारत, भारतीय अदालतें एवं सरकारी महकमें कोई सबक या प्रेरणा लिए बिना अंग्रेजी को स्वतंत्रता के सतहतर साल बाद भी ढोती चली आ रही हैं।

हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई है। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहाँ विषयवस्तु निर्माण की रफ्तार 19 फीसदी है तो हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94 फीसदी है। इसलिए हिंदी को नई सूचना-प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। उनकी भाषा-संस्कृति को समझना होगा तभी वो हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे। बात चाहे राष्ट्र भाषा की हो या राष्ट्र गान या राष्ट्र गीत- इन सबको भी समूचे राष्ट्र में सम्मान एवं स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार को चाहिए कि वह ऐसे आदेश जारी करे जिससे सरकार के सारे अंदरुनी काम-काज भी हिन्दी में होने लगे और अंग्रेजी से मुक्ति की दिशा सुनिश्चित हो जाये। अगर ऐसा होता है तो यह राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने की दिशा में नया भारत-सशक्त भारत बनाने की दिशा में एक अनुकरणीय एवं सराहनीय पहल होगी। ऐसा होने से महात्मा गांधी, गुरु गोलवलकर और डॉ. राममनोहर लोहिया का सपना साकार हो सकेगा। तभी हिन्दी अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकेगी।

आरटीआई : देश के 5 करोड़ ग्रामीण घरों में अब तक नहीं पहुंचा पानी का कनेक्शन

एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने बताया कि 15 अगस्त 2019 से लेकर अब तक साढ़े चार वर्षों में 13,91,70,516 ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं, अगस्त 2019 तक मात्र 3,23,62,838 घरों में ही पानी की आपूर्ति की गई थी।

मोदी सरकार के 'हर घर जल' अभियान के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों में 10 करोड़ ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति की गई है। वहीं, अगस्त 2019 तक सिर्फ तीन करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन पहुंच सका था। हालांकि, अब भी देश के करीब पांच करोड़ घर ऐसे हैं, जहां अब तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है।

एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने बताया कि 15 अगस्त 2019 से लेकर अब तक साढ़े चार वर्षों में 13,91,70,516 ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं, अगस्त 2019 तक मात्र 3,23,62,838 घरों में ही पानी की आपूर्ति की गई थी। बता दें, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 19,25,17,015 (19.25 करोड़) घर हैं। गौरतलब है कि अभियान के बाद से पिछले साढ़े चार वर्षों में 10,68,07,678 (10.68 करोड़) घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। केंद्र का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के गांव के हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने आगे बताया कि अगस्त 2019 तक देश के केवल 16.81 प्रतिशत गावों के घरों में ही पानी का कनेक्शन था, लेकिन पीएम मोदी के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में यह आंकड़ा 72.29 प्रतिशत पहुंच गया है। हालांकि, अब भी कई घर पानी की आस ही देख रहे हैं।

अभियान के तहत झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों के घरों में नल कनेक्शन की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड के मात्र 47.57 प्रतिशत घरों में ही नल का कनेक्शन है तो वहीं राजस्थान में 45.33 प्रतिशत और और पश्चिम बंगाल में 40.69 प्रतिशत ही नल का कनेक्शन है। मंत्रालय का कहना है कि पेयजल का विष्य राज्य का है। आपूर्ति योजनाओं का डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों पर ही निर्भर होता है। भारत सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

नल कनेक्शन में सरकार का बड़ा बजट पेश हुआ

2019-20 में 9,951 करोड़ रुपये
2020-2021 में 10,916 करोड़ रुपये
2021-22 में 40,010 करोड़ रुपये
2022-23 में 54,744 करोड़ रुपये
2023-24 में 47,293 करोड़ रुपये

100 प्रतिशत जल कनेक्शन वाले प्रदेश की सूची : गोवा, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

इन प्रदेशों में 75% से अधिक नल कनेक्शन

मिजोरम (98.35 प्रतिशत)
अरुणाचल प्रदेश (97.83 प्रतिशत)
बिहार (96.42 प्रतिशत)
लद्दाख (90.12 प्रतिशत)
सिक्किम (88.54 प्रतिशत)
उत्तराखंड (87.79 प्रतिशत)
नागालैंड (82.82 प्रतिशत)
महाराष्ट्र (82.64 प्रतिशत)
तमिलनाडु (78.59 प्रतिशत)
मणिपुर (77.73 प्रतिशत)
जम्मू और कश्मीर (75.64 प्रतिशत)
त्रिपुरा (75.25 प्रतिशत)
छत्तीसगढ़ (73.35 प्रतिशत)
मेघालय (72.81 प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश (72.69 प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश (72.37 प्रतिशत)
कर्नाटक (71.73 प्रतिशत)
ओडिशा (69.20 प्रतिशत)
असम (68.25 प्रतिशत)
लक्षद्वीप (62.10 प्रतिशत)
मध्य प्रदेश (59.36 प्रतिशत)
केरल (51.87 प्रतिशत)

आत्मनिर्भरता की भावना से भरा है देश, 2024 में भी गति बनाए रखनी है : मोदी

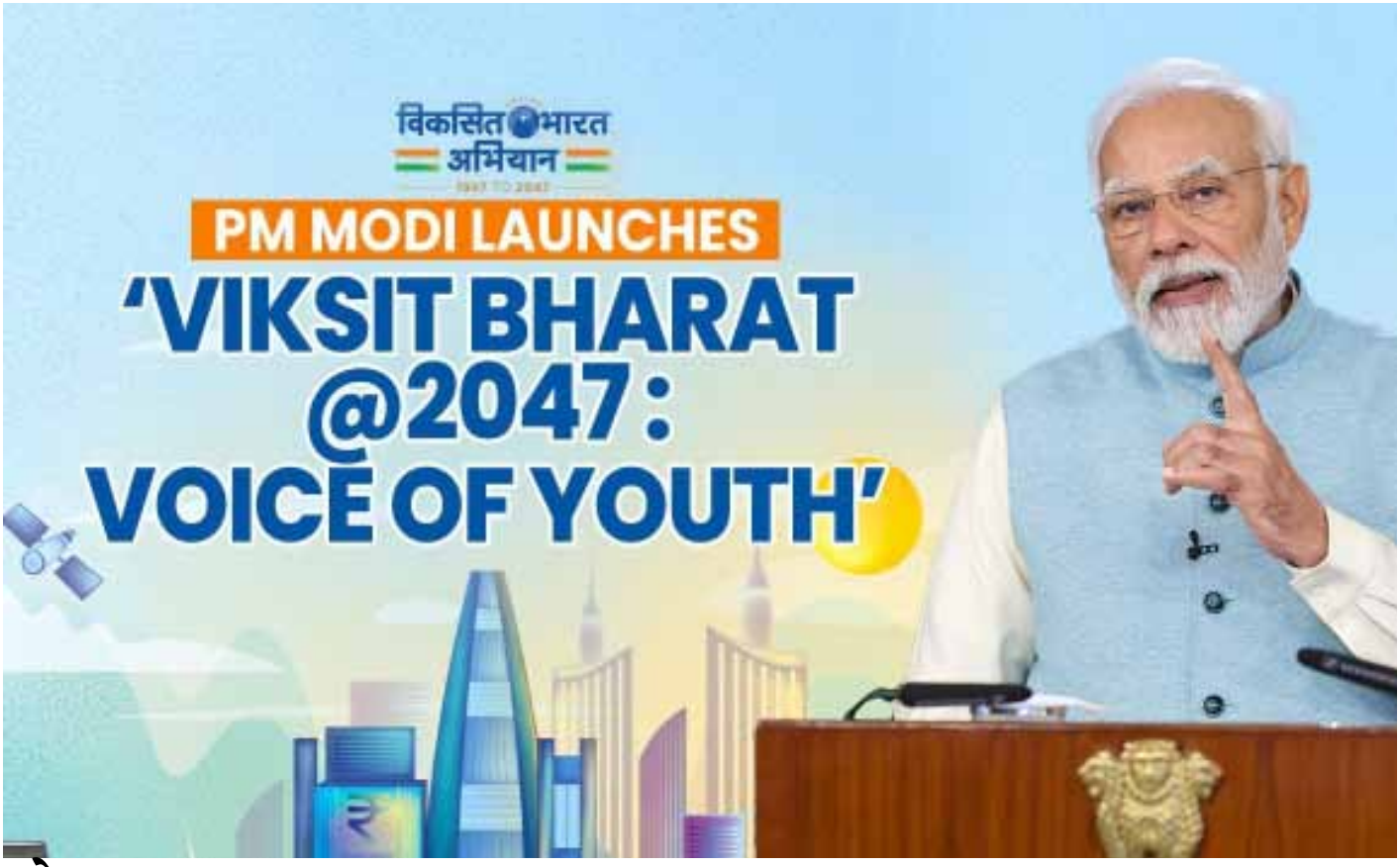

मोदी ने कहा, ''वह दिन दूर नहीं जब किसी एक में संबोधन हुआ करेगा और जनता तत्क्षण उस भाषण को अपनी में सुन सकेगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और उन्हें पंच-प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है तथा इसी मंत्र पर चलते हुए देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। मन की बात के दौरान अक्षय की टिप्पणी का ऑडियो साझा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अक्षय कुमार से पूरी तरह से सहमत हूं, जब वह कहते हैं कि फिट रहने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वह फिट रहने के लिए अच्छा खाने और शुद्ध खाने पर भी जोर देते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना से ओत-प्रोत है तथा इस भावना एवं गति को 2024 में भी बनाए रखना है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया और 'फिट इंडिया' के लिए कई अनूठे प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रसारण के दौरान ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी अच्छी सेहत का राज क्या है। मोदी ने कहा, ''आज भारत का कोना-कोना, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। देश विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना से ओत-प्रोत है।

2024 में भी हमें इसी भावना और गति को बनाए रखना है।'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत का नवोन्मेष का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश अब रुकने वाला नहीं है। मोदी ने कहा, ''जो देश नवोन्मेष को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का नवोन्मेष का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में 81वें स्थान पर थे। आज हम 40वें स्थान पर हैं।'' प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 की सफलता सहित साल 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में देश को हासिल हुई उपलब्धियों का उल्लेख किया और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। दीपावली पर हुए 'रिकार्ड कारोबार' का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बल पर भारत ने इस वर्ष कई विशेष उपलब्धियां हासिल कीं जिनमें चंद्रयान-3 की सफलता और नारी शक्ति वंदन विधेयक का संसद से पारित होना शामिल है।

मोदी ने फिल्म 'आरआरआर' के गीत नाटू-नाटू और लघु वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को ऑस्कर मिलने का जिक्र किया और कहा कि दुनिया ने इनके जरिए भारत की रचनात्मकता को देखा और पर्यावरण के साथ जुड़ाव को समझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा तथा यह तब और ज्यादा होगा जब वे स्वस्थ रहेंगे। मोदी ने हाल में संपन्न काशी-तमिल संगमम का उल्लेख किया और कहा कि इस आयोजन के दौरान उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण 'भाषिणी' का पहली बार उपयोग किया। उन्होंने बताया कि इसकी सहायता से उनके भाषण को उसी समय तमिलनाडु के लोग तमिल में सुन पा रहे थे।

मोदी ने कहा, ''वह दिन दूर नहीं जब किसी एक में संबोधन हुआ करेगा और जनता तत्क्षण उस भाषण को अपनी में सुन सकेगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और उन्हें पंच-प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है तथा इसी मंत्र पर चलते हुए देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। मन की बात के दौरान अक्षय की टिप्पणी का ऑडियो साझा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अक्षय कुमार से पूरी तरह से सहमत हूं, जब वह कहते हैं कि फिट रहने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वह फिट रहने के लिए अच्छा खाने और शुद्ध खाने पर भी जोर देते हैं।

कर राहत बढ़ने की उम्मीद नहीं...

31 जनवरी से बजट सत्र में क्या मिलने की उम्मीद..?

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने आयकर की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था, जिसका बहुत स्वागत किया गया था। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही जाने वाली चार विशेष जातियों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं पेश की जा सकती हैं...

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर नौ फरवरी तक चलेगा। दस दिनों के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और उसी दिन आर्थिक सर्वे पेश किए जाने की संभावना है। दस दिन तक चलने वाला यह बजट सत्र अंतरिम बजट होगा और इसमें सरकार केवल आवश्यक खर्चों के लिए अनुमति मांगेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पेश किए जाने वाले इस बजट के लोकलुभावन नीतियों से भरपूर होने की संभावना है।

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने आयकर की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था, जिसका बहुत स्वागत किया गया था। पिछली बार इस राहत और बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया था। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही जाने वाली चार विशेष जातियों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं पेश की जा सकती हैं।

आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार, इस बार बजट में आयकर सीमा के बढ़ाने की संभावना नहीं है। प्रत्यक्ष आयकर दाताओं की संख्या पहले ही बहुत कम है, इसलिए सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर अपनी आय कम करने की बात नहीं सोचेगी। उसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसे की भी आवश्यकता है। ऐसे में वह अपनी आय कम करने का कोई भी रास्ता नहीं अपनाएगी। हालांकि, किसी नए कर प्रस्ताव के न आने की भी संभावना हो सकती है।

आयकर में बदलाव की संभावना कम

आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. नागेंद्र कुमार शर्मा ने अमर उजाला को बताया कि सरकार की सबसे ज्यादा आय अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से हो रही है। जीएसटी कर संग्रह लगातार 1.50 लाख करोड़ सीमा को पार कर रहा है। इसको और ज्यादा बढ़ाने से सरकार की आय में वृद्धि हो सकती है।

लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे रहें और वे आवश्यक चीजों की बढ़-चढ़कर खरीद करें। ऐसे में सरकार आयकर बढ़ाकर लोगों के हाथों से पैसा कम करने का कोई उपाय नहीं करेगी। लेकिन अपनी आय कम करने के डर से वह आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से बचने की नीति अपना सकती है।

नदियों में बढ़ती गाद से गहराता संकट, जरूरी है इसका प्रबंधन

पिछले महीने संपन्न सतलुज-यमुना जोड़ की बैठक में पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके राज्य में सतलुज नदी अभी से सूख रही है। दिल्ली में यमुना हो या फिर गाजियाबाद-शामली में हिंडन, ये भी सिकुड़ रही हैं। दो महीने पहले बरसात में तबाही मचाने वाली बिहार के गोपालगंज जिले से गुजरने वाली घोघारी, धमई व स्याही नदियों ने भी सूखने के लिए गर्मी का इंतजार नहीं किया। विगत जुलाई में सी-गंगा यानी सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट ऐंड स्टडीज द्वारा जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड की 65 नदियां बढ़ती गाद से हांफ रही हैं।

हालांकि गाद नदियों के प्रवाह का नैसर्गिक उत्पाद है और देश के कई बड़े तीर्थ व प्राचीन शहर इसी गाद पर विकसित हुए हैं। पर नदी के साथ बहकर आई गाद को जब किनारों पर माकूल जगह नहीं मिलती, तो वह जलधारा के मार्ग में व्यवधान बन जाती है। गाद नदी के प्रवाह मार्ग में जमती रहती है और इससे नदियां उथली होती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसी 36 नदियां हैं, जिनकी कोख में इतनी गाद है कि न केवल उनकी गति मंथर हुई है, बल्कि कुछ ने अपना मार्ग बदला और उनका पाट संकरा हो गया। रही-सही कसर अंधाधुंध बालू उत्खनन ने पूरी कर दी। नतीजतन इनमें से कई नदियों का अस्तित्व खतरे में है। प्रयागराज के फाफामऊ, दारागंज, संगम, छतनाग और लीलापुर के पास टापू बनते हैं। संगम के आसपास गंगा नदी में चार मिलीमीटर की दर से हर साल गाद जमा हो रही है।

गंगा की गहराई कम होने से उसकी धारा में भी परिवर्तन हो रहा है। आने वाले दिनों में गंगा की धारा और तेजी से परिवर्तित होगी, क्योंकि जब नदी की गहराई कम हो जाएगी, तो नदी का स्वाभाविक बहाव रुक जाएगा। ऐसे में बाढ़ का खतरा स्वाभाविक है। यह बात सरकारी रिकॉर्ड में है कि आज जहां पर संगम है, वहां यमुना की गहराई करीब 80 फीट है, लेकिन गंगा की गहराई इतनी कम है कि संगम के किनारे नदी में खड़े होकर कोई भी स्नान कर सकता है। पर यमुना की अधिक गहराई के चलते असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तभी संगम पूरब की तरफ बढ़ रहा है और उसका झुकाव अकबर के किले तक खिसक चुका है, जबकि संगम कभी सरस्वती घाट के पास हुआ करता था।

आजादी के बाद भी गढ़मुक्तेश्वर से कोलकाता तक जहाज चला करते थे। गाद के चलते बीते पांच दशक में वहां गंगा की धारा आठ किलोमीटर दूर खिसक गई है। बिजनौर के गंगा बैराज पर गाद की आठ मीटर मोटी परत है। आगरा व मथुरा में यमुना गाद से भर गई है। आजमगढ़ में घाघरा और तमसा के बीच गाद के कारण कई मीटर ऊंचे टापू बन गए हैं। घाघरा, कर्मनाशा, बेसो, मंगई, चंद्रप्रभा, गरई, तमसा, वरुणा और असि नदियां गाद से बेहाल हैं।

बिहार में तो उथली हो रही नदियों में गंगा सहित 29 नदियों का दर्द है। जो नदियां तेज बहाव से आ रही हैं, उनके साथ आए मलबे से भूमि कटाव भी हो रहा है और कई जगह नदी के बीच टापू बन गए हैं। अकेले फरक्का से होकर गंगा नदी पर हर साल 73.6 करोड़ टन गाद आती है, जिसमें से 32.8 करोड़ टन गाद इस बैराज के प्रति प्रवाह में ठहर जाती है। झारखंड के साहिबगंज में गंगा अपने पारंपरिक घाट से पांच किलोमीटर दूर चली गई है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा गठित चितले कमेटी ने साफ कहा था कि नदी में बढ़ती गाद का एकमात्र निराकरण यही है कि नदी के पानी को फैलने का पर्याप्त स्थान मिले, तटबंध और नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण न हो और अत्यधिक गाद वाली नदियों के संगम क्षेत्र से नियमित गाद निकालने का काम हो। पर ये सिफारिशें ठंडे बस्ते में बंद हो गईं। यह दुर्भाग्य है कि विकास के नाम पर नदियों के कछार को सर्वाधिक हड़पा गया। भूमि के लालच में कछार और उसकी गाद लुप्त हो गई। गाद हर नदी का स्वाभाविक उत्पाद है, पर उसका भली-भांति प्रबंधन अनिवार्य है। गाद जैसे ही नदी के बीच जमती है, तो नदी का प्रवाह बदल जाता है। यदि गाद किनारे से बाहर नहीं फैली, तो नदी के मैदान का उपजाऊपन और ऊंचाई, दोनों घटने लग जाते हैं, जिससे बाढ़ का दुष्प्रभाव अधिक होता है।

2023 सुप्रीम फैसलों से भरा

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कई अहम और सालों से लंबित मामलों में फैसला सुनाया। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला भी शामिल है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए जिनका राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दूरगामी असर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अब तक 52 हजार 191 केसों का निपटारा किया है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस साल दर्ज 49 हजार 191 मामलों से 3000 अधिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से ये बात सामने आई है। जबकि 79 हजार 896 मामले अभी तक कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कई अहम और सालों से लंबित मामलों में फैसला सुनाया। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला भी शामिल है। इसके अलावा नए साल 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट अहम मामलों की सुनवाई करने वाला है जिन पर देशभर की नजर होगी।

2023 में ये फैसले यादगार रहे

समलैंगिक विवाह : कानूनी मान्यता देने से इनकार

समलैंगिक शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी। लेकिन पसंद के अधिकार को संवैधानिक आधार करार दिया। ये संवैधानिक बेंच का फैसला था। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की, और LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों पर भी जोर दिया।

अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा। 11 मई को दिए गए फैसले में कहा गया कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में प्रशासनिक सेवा होगी। कहा गया कि चुनी हुई सरकार के पास ही ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण होना चाहिए।

शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मथुरा में तीन गुंबद वाली मस्जिद शाही ईदगाह के लिये एक सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण की मांग के लिये याचिका हिंदू देवता, श्री कृष्ण की ओर से सात लोगों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मूल मुकदमे में दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश पर श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर किया गया था।

... चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मार्च में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल रहेंगे। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर आश्चर्य भी जताया।

2023 में आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है। स्पेशल दर्जा निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थाई प्रावधान भी बताया। संवैधानिक रूप से भारत की शासन संरचना अर्ध-संघीय है। इससे इतर एकात्मक व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित होती है। भारतीय संदर्भ में जबकि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। जस्टिस कौल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, सेनाएं राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए होती हैं, न कि वास्तव में राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन तब ये अजीब समय था। जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 असममित संघवाद का उदाहरण है।

2024 में सुनवाई पर नजर

2024 में इन फैसलों पर होगी नजर

अडानी ग्रुप मामला में फैसला सुरक्षित

अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान याचिकाकर्ता द्वारा सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमिटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को नकार दिया था और कहा कि ऐसे आरोप अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे कि सेबी पर संदेह किया जाए। हम बिना ठोस आधार के सेबी पर अविश्वास नही कर सकते। अब फैसला आना है।

सिंगल अविवाहिता को सेरोगेसी का हक

सिंगल अविवाहित महिला को सरोगेसी का लाभ मिलेगा? इस संवैधानिक सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण का फैसला किया है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि सरोगेसी कानून के उस प्रावधान को खारिज किया जाए जो सिंगल अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिये बच्चे की इजाजत नहीं देता है। । सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी वी. नागरत्ना की बेंच ने केंद्र से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

इलेक्टोरल बॉण्ड पर होगा फैसला

इलेक्टोरल बॉण्ड को चुनौती वाली अर्जी पर सुनवाई के वाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की वेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि ब्योरा पेश करे कि बॉण्ड के जरिये राजनीतिक पार्टियों ने कितना फंड रिसीव किया। कोर्ट ने आयोग के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि उसके पास अभी इस बारे में डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि गोपनीयता का मुद्दा है।

ईडी के हकों पर रिव्यू पिटिशन दाखिल

7 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था के ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, कुकर्की के साथ-साथ सर्च करने का अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थे। तीन जजों की वेंच के सामने केंद्र ने कहा कि उन्हें जवाव के लिए वक्त चाहिए। तब मामले की सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा और वह नई बेंच का गठन करेंगे। नई बेंच सुनवाई करेगी।

दिल्ली में सर्विसेज केस पर हुई सुनवाई

सविसेज मामले में सुप्रीम कोट के फैसले के बाद केंद्र ने नया कानून बनाया। इसके तहत केंद्र ने ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग और ट्रांसफर का प्रावधान किया है। दिल्ली सरकार ने कहा था टैंक संसद ने अब कानून पास कर दिया है ऐसे में में बदलाव चाहते है। अब वह एक्ट को चुनीती देना चाहते हैं। इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करने वाली है।

मुफ्त चुनावी वादों को परखा जाएगा

मुक्त उपहार बाटने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाह की गुहार लगाई गई है। एक फैसले में कहा गया कि राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणपत्र में जो वादा करती है पर करप्ट प्रक्टिस नही है। यानी ने कहा है कि मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले पटिया को मान्यता को रद्द किया जाए।

कई बार राजतिलक होते-होते वनवास हो जाता है, फिर छलका मामा शिवराज का दर्द...

नए आवास का नाम रखा 'मामा का घर'

बच्चे और महिलाएँ भी उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते थे। अपने चुनाव अभियानों में, चौहान ने खुद को महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पेश किया था। उन्होंने लाडली बहना परियोजना के तहत धन जारी करने के लिए एक कार्यक्रम में दो महिलाओं के पैर भी धोए थे, जिन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की थी।

भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलाई, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें किनारे करते हुए मोहन यादव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ताज पहनाया। चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके 64 वर्षीय दिग्गज नेता अगर नजरअंदाज किए जाने से निराश थे तो सार्वजनिक रूप से गुस्से का प्रदर्शन नहीं किया गया। उस समय, खुद को एक निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले चौहान को दिल्ली में भाजपा आलाकमान के आदेश के आगे झुकना अच्छा लग रहा था। लेकिन, जब वह मंगलवार शाम शाहगंज शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनका दर्द साफ तौर पर छलक गया।

भावुक होकर चौहान ने सभा से कहा कि कभी-कभी कोई राज्याभिषेक का इंतजार करता है लेकिन अंत में उसे वनवास मिलता है। पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों के बारे में बात करते हुए, जिसमें लाडली बहना योजना (महिला कल्याण के लिए), लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए आवास योजना शामिल हैं, उन्होंने कहा, 'नई सरकार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी। कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा, कभी-कभी राजतिलक होने तक व्यक्ति को वनवास भी मिल जाता है।' हालाँकि, उन्होंने तुरंत कहा, 'लेकिन यह सब किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है।'

बच्चे और महिलाएँ भी उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते थे। अपने चुनाव अभियानों में, चौहान ने खुद को महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पेश किया था। उन्होंने लाडली बहना परियोजना के तहत धन जारी करने के लिए एक कार्यक्रम में दो महिलाओं के पैर भी धोए थे, जिन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की थी। इस परियोजना के तहत, राज्य में गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,250 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं।

चौहान ने बुधनी सीट पर अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। जहां बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतीं, वहीं कांग्रेस सिर्फ 66 सीटें हासिल कर पाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने नए आवास के बाहर 'मामा का घर' लिखवाया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरे प्यारे बहनों-भाइयों और भांजे-भांजियों, आप सबसे मेरा रिश्ता प्रेम, विश्वास और अपनत्व का है। पता बदल गया है, लेकिन 'मामा का घर' तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूँगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। आपको जब भी मेरी याद आये या मेरी जरूरत हो, निःसंकोच घर पधारिये आखिर यह आपके मामा और भैया का घर जो है।

पांच किलोमीटर लंबा मार्ग हुआ राममयी, नजर आया अयोध्या में बना रामलला का मंदिर...

अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे 18 दिन पहले ब्रह्ममुहूर्त में अहिल्या की नगरी के पश्चिम क्षेत्र का पांच किलोमीटर लंबा मार्ग राममयी नजर आया। रणजीत अष्टमी पर रणजीत हनुमान मंदिर से निकली प्रभातफेरी में हर तरफ भगवा ही नजर आया। सुबह पांच बजे निकली इस प्रभातफेरी को महूनाका पहुंचने में करीब तीन घंटे लगे। हर तरफ सिहंस्थ सा नजारा दिखाई दिया।

हर तरफ जय श्रीराम और जय रणजीत के नारे लगते रहे। हर तरफ प्रभु श्रीराम नजर आए। इसके लिए खास तैयारी की गई थी, जहां इसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की वृहद प्रतिकृति रही। 40 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी और 21 फीट ऊंचाई है। प्रभातफेरी के लिए 125 स्वागत मंच लगाए गए थे और हर स्वागत मंच पर प्रभु श्रीराम के दर्शन हुए। पूरा मार्ग भगवा ध्वजों से सजाया गया था। इसी के साथ चार दिनी रणजीत अष्टमी महोत्सव का समापन भी हो गया। इसकी व्यवस्था निस्वार्थ भाव से जुड़े रणजीत भक्त मंडल के 2 हजार सदस्यों ने संभाली। मंडल में 22 हजार रजिस्टर्ड सदस्य हैं। इस भक्त मंडल की खासियत है कि इसमें कोई पदाधिकारी नहीं बल्कि सभी समान रणजीत बाबा के भक्त है।

मुख्य पुजारी पं. दीपेश व्यास ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा का अवसर हर सनातनी के लिए खास होती है। इसके चलते इस बार रणजीत अष्टमी महोत्सव को भगवान श्रीराम को समर्पित किया गया था।

प्रभातफेरी रणजीत हनुमान मंदिर, द्रविड नगर, महू नाका चौराहा से घूमकर अन्नपूर्णा मंदिर रोड पर पहुंची। इसके बाद नरेंद्र तिवारी मार्ग से होते हुए पुनः रणजीत हनुमान मंदिर पर पहुंची।

अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर की विशाल प्रतिकृति का निर्माण बंगाल के 10 कलाकारों द्वारा एक माह में किया गया। इसका निर्माण लोहा, लकड़ी, कपड़ा, थर्माकोल से किया गया। इसे डिजाइनर जाली और रंगों से सजाया गया। यह प्रतिकृति को 16 पहिए वाली गाड़ी पर रखकर झांकी की तरह प्रभातफेरी में शामिल किया गया था।

प्राचीन मंदिर की 137 साल पुरानी परंपरा

रणजीत हनुमान मंदिर से प्रभातफेरी निकालने की परंपरा 137 साल पुरानी है जो आज भी जारी है। इसकी शुरुआत पं. भोलाराम व्यास ने की थी। उस समय हाथ में रणजीत हनुमान की तस्वीर लेकर मंदिर परिसर में पैदल सात परिक्रमा लगाई जाती थी। इसके बाद प्रभातफेरी ठेला गाड़ी पर निकाली जाने लगी। 2012 के बाद प्रभातफेरी के स्वरूप वृहद हुआ और बाबा को बग्घि में बैठाकर घूमाया जाने लगा। 2014 में बाबा का विग्रह तैयार कर स्वर्ण रथ पर प्रभातफेरी निकाली जाने लगी। प्रभातफेरी में 75 हजार से अधिक भक्त शामिल होते हैं। रणजीत अष्टमी महोत्सव में बुधवार को 51 हजार रक्षासूत्रों को अभिमंत्रित किया गयाा। इन रक्षा सूत्र को निश्शुल्क वितरित किया गया। इससे पहले सुबह रणजीत बाबा के उत्सव विग्रह का महाभिषेक किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आपके आंगन तक आई है : राज्यपाल

राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सूठोद में शामिल हुए। यात्रा के दौरान आयोजित शिविर में राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आपके आंगन तक आई है। इसका लाभ जरूर उठाएं। देश बहुत अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कार्यालयों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब संकल्प यात्रा के माध्यम से अधिकारी स्वयं नागरिकों के पास पहुंच कर उनका आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जहां पक्के मकान बनाये जा रहे हैं, वहीं गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत निरामय योजना से दिया जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इसमें हम सभी का योगदान आवश्यक है। स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। समूह की महिलाएं भी अब 15 से 20 हजार महीने के कमा रही है। आजीविका के माध्यम से महिलाओं को विश्वास, साहस, और पैसा मिल रहा हैं। अब एक-एक योजनाओं की एक-एक स्टोरी और कहानी बन रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में 16 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ऐसे जरूरतमंद और पात्र नागरिक, जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं के हितलाभ से वंचित रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। महिलाएं अब अपने परिवार की उन्नति में भी योगदान दे रहीं हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति एवं अटल पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्जवला जैसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अभिनव पहल हैं।

राज्यपाल श्री पटेल द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। नन्ही बालिका विश्वेश्वरी भट्ट द्वारा कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण रामायण सुनाने पर राज्यपाल ने पुरस्कृत किया गया। महामहिम राज्यपाल श्री पटेल ने उपस्थित जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने तथा नागरिक कर्तव्य निभाने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरकारी विभागों पर निगम का करोड़ों बकाया, अब पत्र लिखकर पैसा जमा करने को कहेंगे

आर्थिक संकटों से जूझ रहा नगर निगम एक तरफ तो आमजन पर छोटे-छोटे बकाया भुगतान को जमा कराने के लिए दबाव बनाता है दूसरी तरफ उसका सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपया बकाया है लेकिन वह कुछ नहीं करता। रेलवे, पुलिस विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयडीए सहित कई सरकारी विभाग है जिन पर नगर निगम को संपत्तिकर और सेवा प्रभार के रूप में करोड़ों रुपये लेना निकल रहे हैं। ये बकाया एक दो दिन का नहीं बल्कि वर्षों का है, लेकिन कभी कोई वसूली की कार्रवाई नहीं हुई।हालांकि नगर निगम अब विभागों पर निकल रहे बकाया कि वसूली का दावा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हम मूल विभागों को पत्र जारी कर उन्हें बता रहे हैं कि इंदौर में उनका क्या-क्या संपत्ति है और कितना कर बकाया है। पत्र में हमने विभागों के प्रमुख से कर जमा कराने को भी कहा है।

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार अकेले रेलवे से ही नगर निगम को करीब 56 करोड़ रुपये लेना बाकी हैं। इसमें से 47 करोड़ रुपये संपत्तिकर के रूप में और 9 करोड़ रुपये विज्ञापन शुल्क के रूप में वसूलना है। बीएसएफ से निगम को 17 करोड़ रुपये विभिन्न कर और प्रभार के रूप में लेना हैं। इसके अलावा निगम के बड़े बकायादारों में पुलिस विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयडीए भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक से निगम को करोड़ों में कर वसूलना है।

हम पत्र लिखकर कर जमा करने को कह रहे हैं

हमने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर नगर निगम के बकाया कर जमा करने को कहा है। कुछ जगह संपत्ति कर की राशि को लेकर विवाद भी है। हम उसका निराकरण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही बकाया कर वसूल लेंगे।

- अभिलाष मिश्रा, अपर आयुक्त राजस्व, नगर निगम इंदौर

लोकसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों के लिए

सांसदों को 50 और विधायकों को मिलेंगे 15-15 करोड़ रुपये

अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इसके लिए 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रविधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें।

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अधिकतर सांसद और विधायक अपनी निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग कर चुके हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने कई वादे भी किए। विधायक निधि तो

नए वित्तीय वर्ष में मिलेगी पर इसके पहले लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने सांसद और विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आचार संहिता लागू होने के पहले भूमिपूजन कार्यक्रम हो सकें।

सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन पर रहेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपये तक के कामों के प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राथमिकता से लिए जाएंगे। दरअसल, सरकार का जोर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उधर, सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे सांसद और विधायकों के माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों का आगामी वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता दें। लोक निर्माण विभाग ने तो आश्वस्त भी कर दिया है कि जो प्रस्ताव मिलेंगे उनका तकनीकी परीक्षण कराकर एक साथ निविदा आमंत्रित कर ली जाएंगी।

सभी पिछोर नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अध्यक्ष
श्रीमती सीमा व्रजेंद्र सिंह राजपूत

उपाध्यक्ष
श्रीमति बैशाली पिता बृजगोपाल लोया

महेश पुरोहित (सीएमओ)
उदयपुरा नगर परिषद

अपील

1 निकाय द्वारा जारी कंप्यूटरीकृत संपत्ति कर जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर ऐसा समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।

2 जल ही जीवन है जल का दुरुपयोग ना करें।

3 भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।

4 नगर परिषद की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करें।

5 नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें कचरा नियत स्थानों पर ही डालें।

6 जन्म मृत्यु का पंजीयन समय पर कराएं तथा निकाय से कंप्यूटरीकृत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

7 नगर परिषद से अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें।

8 शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

9 नगर में वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करें।

परिजनों के इनकार पर ICU में भर्ती नहीं कर सकते अस्पताल : अदालत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती करने से जुड़े अपने ताजा दिशा-निर्देश में यह जानकारी दी

दिशा-निर्देश में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जिन स्थितियों में आईसीयू में नहीं भर्ती करने के लिए कहा गया है उनमें मरीज या मरीज के परिजनों की ओर आईसीयू में भर्ती से इनकार करना, कोई बीमारी जिसके इलाज की सीमा है, आईसीयू देखभाल के खिलाफ किसी व्यक्ति की ओर से पूर्व में दिये गये लिखित दस्तावेज (वसीयत) या उन्नत निर्देश और महामारी या आपदा की स्थिति में जब संसाधन (बिस्तर, उपकरण, कर्मचारी आदि) की कमी हो तब निरर्थकता और कम प्राथमिकता मानदंडों के तहत आने वाले लाइलाज रोगी शामिल हैं।

अस्पताल गंभीर रूप से बीमार रोगियों को उनके या उनके परिजनों के इनकार करने पर गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में नहीं भर्ती कर सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती करने से जुड़े अपने ताजा दिशा-निर्देश में यह जानकारी दी है। 24 विशेषज्ञों की ओर से तैयार दिशा-निर्देश में सिफारिश की गई है कि यदि लाइलाज मरीज या बीमारी का इलाज संभव नहीं है या उपलब्ध नहीं है और माजूदा उपचार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, खासकर मरीज के जीवित रहने के लिहाज से, तो आईसीयू में रखना व्यर्थ की देखभाल करना है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई आईसीयू में देखभाल के खिलाफ है तो उस व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा महामारी या आपदा की स्थिति में, जब संसाधन की कमी होती है, कम प्राथमिकता वाले मानदंडों को एक मरीज को आईसीयू में

रखने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड किसी अंग का काम करना बंद करना और मदद की आवश्यकता या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए। जिन मरीजों ने हृदय या श्वसन अस्थिरता जैसी किसी बड़ी 'इंट्राऑपरेटिव' जटिलता का अनुभव किया है या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, वे भी मानदंडों में शामिल हैं। दिशा-निर्देश में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जिन स्थितियों में आईसीयू में नहीं भर्ती करने के लिए कहा गया है उनमें मरीज या मरीज के परिजनों की ओर आईसीयू में भर्ती से इनकार करना, कोई बीमारी जिसके इलाज की सीमा है, आईसीयू देखभाल के खिलाफ किसी व्यक्ति की ओर से पूर्व में दिये गये लिखित दस्तावेज (वसीयत) या उन्नत निर्देश और महामारी या आपदा की स्थिति में जब संसाधन (बिस्तर, उपकरण, कर्मचारी आदि) की कमी हो तब निरर्थकता और कम प्राथमिकता मानदंडों के तहत आने वाले लाइलाज रोगी शामिल हैं।

महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी : केंद्र सरकार

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी श्रिनिवास ने कहा, ''यह संशोधन प्रगतिशील प्रकृति का है और पारिवारिक पेंशन के मामलों में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन साथी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

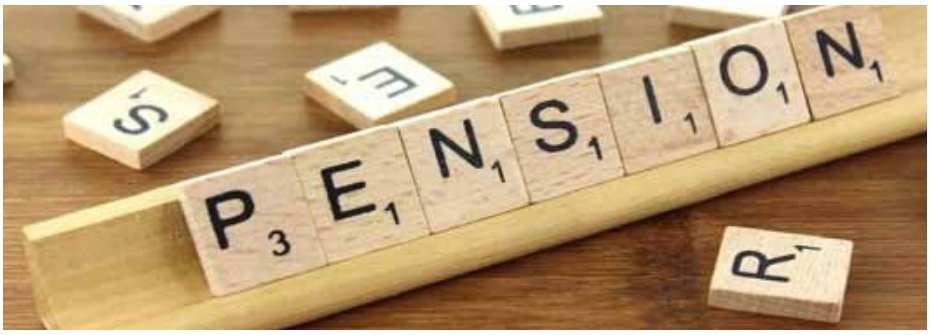

(डीओपीपीडब्ल्यू) ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सचिव वी श्रिनिवास ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, '' उन सभी मामलों में जिनमें तलाक की याचिका दायर की गई है या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले शामिल हैं, यह संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन पति के बजाय उसके पात्र बच्चे को वितरित करने की अनुमति देता है।

मध्यप्रदेश में नए सिरे से निर्धारित होंगी थानों-चौकियों की सीमाएं

प्रदेशभर में थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। 31 जनवरी के पहले यह काम पूरा करने के निर्देश गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी को दिए हैं। फरवरी में सीमाओं के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सोमवार को खरगोन में संभागीय बैठक में प्रदेश के थानों की सीमाओं का पुनर्निधारण करने के निर्देश दिए थे। पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में आम नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए हर जिले में बनी समिति द्वारा फोन नंबर भी जारी किया जा रहा है। गृह विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। दरअसल, आबादी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में नए थाने बन रहे हैं, पर सीमाओं का पुनर्निधारण नहीं होने से कई व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं कि नया जिला बनने पर पुलिस थाना दूसरे जिले में चला गया , जिससे राजस्व जिला अलग और पुलिस जिला अलग हो गया। सीमाओं के पुनर्गठन में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि दूर गांव या कस्बे को उनके नजदीक के थाने में जोड़ा जाए, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे।

थानों की सीमाओं का निर्धारण मुख्य रूप से वहां की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस क्षेत्र में अपराध कितने घटित हो रहे हैं। साथ ही सुरक्षा और वीवीआइपी मूवमेंट को भी ध्यान रखा जाता है।

-अरुण गुर्टू सेवानिवृत डीजी पुलिस

अपने विभागों का सप्ताह में 3 बार निरीक्षण करेंगे अपर आयुक्त

अपने चैंबरों से ही पूरे शहर की व्यवस्था संभालने वाले नगर निगम के अफसरों को अब सप्ताह में तीन बार बाहर निकलना होगा। नगर निगम आयुक्त फैंक नोबल ए ने सभी अपर आयुक्तों को निर्देश दिए कि अब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सभी को अपने विभाग के साथ शाखाओं का औचक निरीक्षण करने के साथ कामकाज की समीक्षा करनी होगी। सप्ताहभर अधिकारियों ने क्या किया? इसकी रिपोर्ट खुद आयुक्त देखेंगे।

दरअसल नगर निगम के सभी अपर आयुक्तों के चैंबर आईएसबीटी में हैं। जबकि शहर के हर इलाके में निगम का अपना दफ्तर है। हर वार्ड में एक वार्ड कार्यालय के हिसाब से 85 वार्ड कार्यालय हैं। वहीं 21 जोन कार्यालयों के दफ्तरों के अलावा 21 ही सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों के दफ्तर, 11 नागरिक सुविधा केन्द्र, यांत्रिक विभाग का स्मार्ट सिटी मुख्यालय के पास अलग हेड क्वाटर, वाटर वर्कस के करीब 10 दफ्तर, दो वर्कशॉप, शाहपुरा में बिल्डिंग परमिशन शाखा का मुख्यालय, फतेहगढ़ में फायर कंट्रोल रूम हेड क्वाटर के साथ ही अलग-अलग इलाकों में फायर सब स्टेशन, न्यू मार्केट में जनसंपर्क और वाचनालय का हेड क्वाटर

है। ऐसा कोई इलाका नहीं, जहां निगम के दफ्तर नहीं हैं। नगर निगम के अपर आयुक्तों को ही अपने कई दफ्तरों के पते नहीं मालूम। हाल ही में जब इसकी जानकारी निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए को पता चली तो उन्होंने सभी अपर आयुक्तों अपने-अपने अधीनस्थ विभागों, शाखाओं का सप्ताह में तीन बार निरीक्षण करने को कहा। आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड भी अपडेट रखे और कर्मचारियों की वेतन कटौती, कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण, वेतन वृद्धि रोकने का काम तुरंत करें। जीएडी से कहा कि कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश में ट्रांसफर के बाद खाली पद पर किस कर्मचारी से काम लिया जाएगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख आदेश में करें।

लोकसभा चुनाव के लिए BJP का मास्टर प्लान तैयार

मध्यप्रदेश में शाह और गडकरी जैसे दिग्गज संभालेंगे मोर्चा...

अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए भाजपा की लोकसभा चुनाव योजना बैठक गुरुवार को सीहोर के एक रिसार्ट में हुई। बैठक में तय किया गया कि प्रदेश की 29 संसदीय सीटों को सात अलग-अलग क्लस्टर में बांटा जाएगा। क्लस्टर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेता समय समय पर यहां आकर मोर्चा संभालेंगे। मालवांचल के एक क्लस्टर में पांच सीटें रखी गई हैं, बाकी में चार-चार। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक मंत्री और एक संगठन का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया।

10 हजार नुक्कड़ सभाएं कराएगा भाजयुमो

यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अपने अपने वर्ग में जाकर नीचे तक लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा को चुनाव पूर्व 10 हजार नुक्कड़ सभाएं करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि हमें किसी भी तरह की गलतफहमी न पालकर खुद को लोकसभा चुनाव में झोंक देना है। चुनाव प्रचार पूरी तरह सादगी भरा होगा, ताम-झाम के बजाए लोगों से संपर्क और संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का भी सुझाव दिया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं के हर हितग्राही से संपर्क करने का भी निर्णय लिया गया। शिवप्रकाश ने कहा, हमें अति आत्मविश्वास से बचना है पार्टी नेताओं ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58 प्रतिशत वोट मिले थे, इस बार इससे भी अधिक वोट मिलना चाहिए। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि हमें अति आत्मविश्वास से बचना है।

विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा : विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई और जिन 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा को पराजय मिली, उन सीटों के हर बूथ पर वोट शेयर 51 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया।ऐसी सीट हैं, जहां भाजपा को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कम वोट मिले हैं। इनमें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसी तरह मुरैना की पांच, भिंड की चार, ग्वालियर की चार, टीकमगढ़ की तीन, मंडला की पांच, बालाघाट की चार, रतलाम की चार, धार की पांच और खरगोन लोकसभा क्षेत्र की आठ विधानसभा सीटों में से पांच पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।

हर लोकसभा क्षेत्र से 10 हजार लोगों को ले जाने का लक्ष्य

बैठक में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे आगे आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। हर लोकसभा क्षेत्र से 10 हजार लोगों को अयोध्या ले जाने की योजना बनाई गई है। सरकार बनने के बाद भाजपा और संघ पदाधिकारियों की यह पहली बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डा. सत्यनारायण जटिया मंचासीन रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं जगदीश देवड़ा, प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, मोर्चो के अध्यक्ष एवं अपेक्षित श्रेणी के नेतागण उपस्थित थे।

भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी संस्थानों को अपने खर्च पर लगाने होंगे CCTV

मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान, जहां भीड़भाड़ होती है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल और सिनेमाघर संचालकों को स्वयं के व्यय पर इसकी व्यवस्था करनी होगी। इन्हें दो माह तक न केवल डाटा सुरक्षित रखना होगा बल्कि जब भी पुलिस को जांच के लिए आवश्यकता होगी तो इसे अनिवार्य रूप से देना होगा। सभी संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए समय दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में यदि व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर आर्थिक दंड लगेगा।तत्कालीन शिवराज सरकार के समय नवंबर 2022 में लोक सुरक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए गृह विभाग ने लोक सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी की थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों से तेलंगाना के अधिनियम का अध्ययन भी कराया गया पर इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

अब मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने इंदौर संभाग के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपराध पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह विभाग ने एक बार फिर नगरीय क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी विधेयक की तैयारी को शुरू कर दी है। शुरुआत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों से की जाएगी और फिर इसका विस्तार होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस काम को देखेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा।

भवन अनुज्ञा में किया जा सकता है प्रविधान : विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल और सिनेमाघर सहित जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, वहां सुरक्षा के लिए संचालकों से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। जिला और नगरीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह संचालकों से चर्चा करके सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें एक-दो माह का समय भी दिया जाएगा। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि नए बनने वाले शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल, सिनेमाघर की भवन अनुज्ञा में ही सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता का प्रविधान कर दिया जाए।

लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को पैसे हस्तांतरित करने से कांग्रेस को पीड़ा : सीएम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डेटा साझा करते हुए कहा कि विभिन्न कारणों से पिछले साल सितंबर से लाभार्थियों की संख्या में 1.75 लाख की गिरावट आई है। अग्रवाल ने कहा किअन्य बातों के अलावा, लगभग 1.56 लाख महिलाएं 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद अपात्र हो गईं, जबकि 18,000 से अधिक महिलाओं ने लाभ छोड़ दिया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की 'लाडली बहना' योजना के तहत महिलाओं को धनराशि हस्तांतरित करने से कांग्रेस को पीड़ा होती है। वह एक समारोह को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत 1.29 करोड़ लाभार्थियों को 1,576 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। कांग्रेस ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया था कि क्या नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई योजना, यादव द्वारा चौहान की जगह लेने के बाद भी जारी रहेगी। यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार सांकेतिक रूप से 'माउस के एक क्लिक' से इस योजना के तहत धन

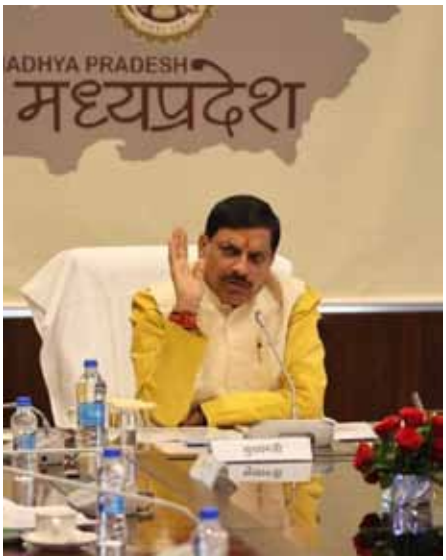

हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि जब सरकार पैसे ट्रांसफर करती है तो कांग्रेस नेताओं को दर्द क्यों होता है। उन्होंने (कांग्रेस) कहा कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। अब जब सरकार पैसा ट्रांसफर कर रही है तो कहने लगते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हम ऐसा करना जारी रखेंगे और उनका दर्द जारी रहेगा।'' योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1250 रुपये देती है। इस बीच, कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने दावा किया कि चौहान सरकार के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, और अब यह घटकर 1.29 करोड़ हो गई है। मिश्रा के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राज्य भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ''झूठ की फैक्टरी'' है।

उन्होंने डेटा साझा करते हुए कहा कि विभिन्न कारणों से पिछले साल सितंबर से लाभार्थियों की संख्या में 1.75 लाख की गिरावट आई है। अग्रवाल ने कहा किअन्य बातों के अलावा, लगभग 1.56 लाख महिलाएं 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद अपात्र हो गईं, जबकि 18,000 से अधिक महिलाओं ने लाभ छोड़ दिया।

सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो कम से कम छह माह से अलग रहना जरूरी

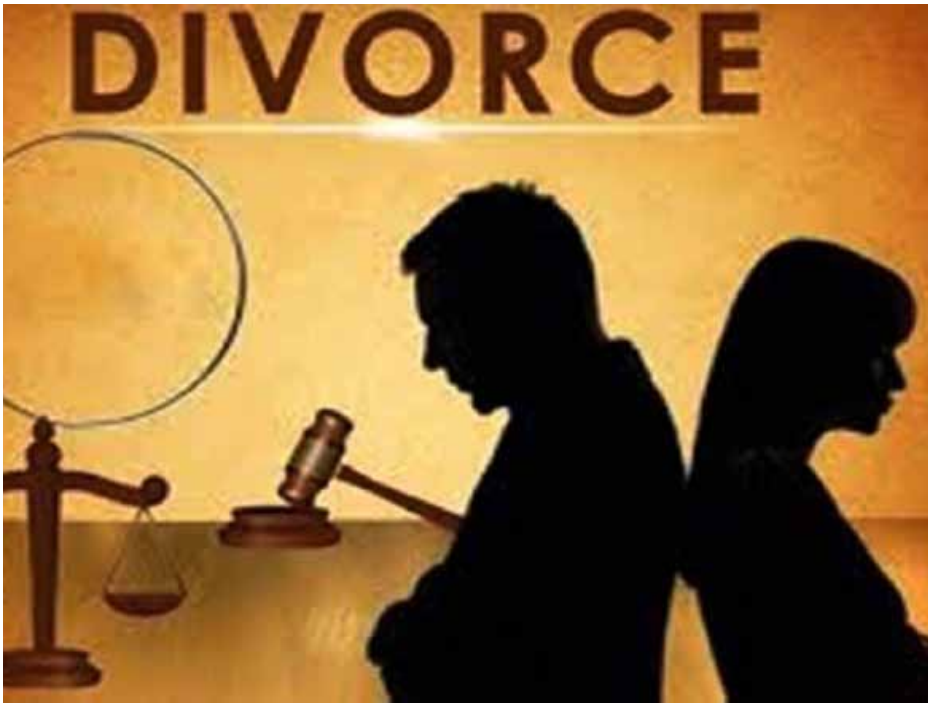

पति-पत्नी अगर आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के प्रविधानों के तहत यह जरूरी है कि उनकी शादी को कम से कम एक वर्ष पूरा हो गया हो और वे कम से कम छह माह से अलग-अलग रह रहे हों। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पति-पत्नी दोनों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत एक साथ न्यायालय में आवेदन देना होता है। एडवोकेट सिद्धार्थ सिसोदिया ने बताया कि शादी को अगर एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो आपसी सहमति से तलाक का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह बात भी ध्यान रखें कि आपसी सहमति से तलाक का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद पति-पत्नी दोनों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। आवेदन के साथ पति-पत्नी के पृथक-पृथक शपथ पत्र, विवाह पत्रिका, फोटोग्राफ आदि संलग्न करना होता है। आवेदन पत्र 100 रुपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए प्रस्तुत आवेदन में इस बात का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए कि पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक आखिर क्यों लेना चाहते हैं और उनके बीच कोई विवाद नहीं है। आपसी सहमति से तलाक का आवेदन जहां विवाह हुआ वहां, जहां रहते हुए पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ वहां और जहां उन्होंने अलग-अलग रहना शुरू किया हो या जहां पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही हो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत कर सकते हैं।

भरण पोषण की राशि को भी ध्यान में रखा जाता है

आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए प्रस्तुत आवेदन के निराकरण में न्यायलय भरण पोषण की राशि देने के संबंध में पति-पत्नी के बीच हुए समझौते को भी ध्यान में रखता है। कई मामलों में पति भरण पोषण की एक मुश्त राशि आवेदन के साथ ही पत्नी को दे देता है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो प्रतिमाह भरण पोषण की राशि तय की जाती है। प्रविधान यह है कि पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात भरण पोषण की राशि तब तक ही मिलती है जब तक की वह दूसरा विवाह न कर ले या नौकरी, व्यवसाय से अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त आय न अर्जित करने लगे। आपसी सहमति से होने वाले तलाक के समझोते में इस विवाह से उत्पन्न संतान का पालन पोषण के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश होते हैं कि पति-पत्नी में से संतान की देखभाल कौन करेगा। कुछ समय पहले तक यह नियम था कि आपसी सहमति का आवेदन प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट छह माह कूलिंग पीरियड के रूप में देती थी ताकि पति-पत्नी अगर विवाद के बाद भी साथ रहना चाहे तो परिवार टूटने से बच सके, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार आपसी सहमति से तलाक के लिए प्रस्तुत आवेदन के निराकरण में कुलिंग पीरियड की आवश्यकता नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जहां पति-पत्नी के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं हो वहां विचारण न्यायालय स्वविवेक से 6 माह के कुलिंग पीरियड की अवधि को समाप्त कर सकता है।

जबलपुर-ग्वालियर में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नरी

लोस चुनाव से पहले होगा अमल

सरकार लोकसभा चुनाव के पहले ग्वालियर और जबलपुर शहर में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में दोनों महानगरों में आयुक्त व्यवस्था लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री डा. यादव ने भी पदभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद एक्स हैंडल पर पर पोस्ट में लिखा था कि ''मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था का है संकल्प। भोपाल एवं इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली।'' इसके बाद गृह विभाग ने भी मुख्यमंत्री की बात को दोहराते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि भोपाल और इंदौर के बाद अब ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी।

एसपी को तैयारी के निर्देश

दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तैयारी शुरू करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कहा है। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद दोनों शहरों में व्यवस्था लागू हो जाएगी। बता दें कि पुलिस आयुक्त व्यवस्था में पुलिस को भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अधिकार मिल जाते हैं। वह अपराधियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। मौजूद अधिकारियों के पदनाम भी आयुक्त व्यवस्था के अनुसार हो जाएंगे। बता दें कि महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। भोपाल और इंदौर में 21 नवंबर 2021 से यह व्यवस्था लागू है। अब ग्वालियर और जबलपुर शहर में इसे लागू करने के लिए सबसे बड़ा काम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के थानों का परिसीमन होगा।

पुलिस कमिश्नर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं?

- पुलिसकर्मियों का तबादला का अधिकार
- लाठी चार्ज या फायरिंग का आदेश देने का अधिकार
- कानून-व्यवस्था संबंधी अधिकार
- शस्त्र लाइसेंस देने का अधिकार
- बार लाइलेंस जारी करने का अधिकार
- होटलों का लाइसेंस जारी करने का अधिकार
- धरना प्रदर्शन की इजाजत देने का अधिकार
- लाठी चार्ज पर फैसला करने का अधिकार
- पुलिस बल की संख्या तय करने का अधिकार

भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार

जगन्नाथ मंदिर में नए साल से...

फटी जींस, स्कर्ट और निकर पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

देवी-देवताओं से जुड़ी रस्में निभाने के लिए कुछ वक्त तक दर्शन रोक दिए गए थे।'' अधिकारियों ने बताया कि नव वर्ष पर शहर में यातायात संबंधी पाबंदियां लगायी गयी हैं। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भी सोमवार से पान और तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तंबाकू या पान चबाते पाए गए श्रद्धालुओं को 11वीं सदी के इस शिव मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगायी गयी है।

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने 12वीं सदी के इस धार्मिक स्थल में निकर, फटी जींस, स्कर्ट और बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश करने पर रोक लगा दी और उनके लिए 'ड्रेस कोड' अनिवार्य कर दिया है। उसने नव वर्ष से मंदिर परिसर में गुटखा और पान खाने तथा प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर भी पूर्ण रोक लगा दी है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश

करने के लिए ''शालीन वस्त्र'' पहनने होंगे। हाफ पैंट, निकर, फटी हुई जींस, स्कर्ट और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस नियम के लागू होने से 2024 के पहले दिन मंदिर आ रहे पुरुष श्रद्धालुओं को धोती और तौलिया पहने हुए देखा गया और महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज में नजर आईं। एसजेटीए ने पहले इस संबंध में एक आदेश जारी किया था और पुलिस से इन पाबंदियों को लागू करने के लिए कहा था। अधिकारी ने बताया कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में गुटखा और पान खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस बीच, नव वर्ष के दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले गए जो देर रात एक बज कर 40 मिनट से ही ग्रांड रोड पर कतार में खड़े हो गए थे।

साल के पहले दिन दर्शन के लिए खजराना

गणेश मंदिर पहुंचे साढ़े 4 लाख श्रद्धालु

अहिल्या की नगरी के खजराना गणेश मंदिर में नए साल के पहले दिन सोमवार को साढ़े चार लाख भक्त पहुंचे और नववर्ष का श्रीगणेश किया। सुबह पांच बजे से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला देर रात तक चला। इस खास अवसर के लिए भगवान का आकर्षक शृंगार किया गया था। भक्त चार-चार की कतार में चलित दर्शन कर रहे थे। इस दौरान सतत जय गणेश के जयघोष लगाए जा रहे थे। दर्शन व्यवस्था 60 सुरक्षाकर्मियों के साथ वालेंटियर और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने भी संभाली। भगवा ध्वजा से सजे रणजीत हनुमान मंदिर में पहुंचे एक लाख श्रद्धालु- रणजीत हनुमान मंदिर में भी एक लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों को 20 मिनट में दर्शन की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर भगवा ध्वजा से पूरे मंदिर को सजाया गया था। चार-चार की कतार में दर्शन की व्यवस्था थी। इसके अलावा पितृ पर्वत सहित इंदौर के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही।

प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जा सकेगी दवाइयां, आर्गन ट्रांसपोर्टेशन होगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार के जीपीओ चौराहे पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) उप क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह देश की आठवीं और प्रदेश की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है। उन्होंने वर्चुअली एम्स भोपाल में पांच आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। 2.7 करोड़ रुपये की लागत से बना हड्डियों का घनत्व नापने वाला डेक्सा स्कैन, वायरल लोड जांचने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की लागत से बना कोबाल्ट 5800 सिस्टम, दो करोड़ की लागत से बना ट्रामा और इमरजेंसी आपरेशन थियेटर कांप्लेक्स, ड्रोन स्टेशन जिससे आदिवासी क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंचाई जा सकेंगी, दो करोड़ रुपये की लागत से बना 16 कमरे वाला प्राइवेट वार्ड काम्प्लेक्स, जिनके माध्यम से आम जनता तक सारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी और चार करोड़ की लागत से बना जिम कांप्लेक्स का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रयोगशाला के माध्यम से निर्मित की जा रही दवाइयों का मानक सुनिश्चित करने में आसानी होगी। अब प्रदेश की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भारत सरकार के अप्रूवल के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वे इंदौर से ही अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकेंगे। इंदौर फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क का भी निर्माण हो रहा है। जल्द ही मेडिकल डिवाइस परीक्षण प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद शंकर लालवानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी, एम्स भोपाल के सीईओ अजय सिंह आदि मौजूद रहे।

ड्रोन से पहुंचेंगे अंग

उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम खेतों में ड्रोन का उपयोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। ड्रोन के माध्यम से हम न केवल दूरस्थ क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंच सकेंगे लेकिन आपातकालीन स्थिति में रक्त पहुंचना, ब्लड सैंपल लेना एवं आर्गन ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकेगा। यह सब दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है।

केंद्र सरकार भरेगी निर्धन कैदियों का अर्थदंड, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मांगी जानकारी

केंद्र सरकार ऐसे निर्धन कैदियों का अर्थदंड और जमानत राशि का व्यय वहन करेगी तो इसे नहीं दे पाने के कारण जेल में हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने प्रमुख सचिव, जेल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की है। यह समिति गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि और दोष सिद्ध कैदियों की जुर्माना राशि आदि भुगतान के संबंध में जिला स्तरीय साधिकार समिति से प्राप्त अनुशंसाओं पर निर्णय लेगी। इसी तरह जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। राज्य सरकार प्रदेश के निर्धन कैदियों का डाटा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजेगी।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्धन कैदियों को सहायता दिए जाने की योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी है। मंत्रालय ने ऐसे कैदियों की संख्या भी मांगी है। बता दें, अभी तक मध्य प्रदेश की जेलों में निर्धनता के कारण अर्थदंड न भरने वाले कैदियों के लिए जेल मुख्यालय गैर सरकारी संगठन, निजी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से राशि लेकर इन निर्धन कैदियों को रिहा कराने की पहल करता रहा है। निर्धन कैदियों की जमानत के लिए 40 हजार रुपये की राशि कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति स्वीकृत कर सकेगी। वहीं अर्थदंड भरने के लिए 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। इससे अधिक की राशि होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। अधिकतम राशि की वर्तमान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हालांकि इस व्यवस्था में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्स्टांसेस) एक्ट, पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फार सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट), पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग) और यूएपीए एक्ट (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के निर्धन कैदियों को केवल जमानत के लिए आर्थिक मदद की जाएगी उनका अर्थदंड नहीं भरा जाएगा।

कान्ह-सरस्वती नदी में अपशिष्ट छोड़ने वाली 9 फैक्ट्रियों पर जिला प्रशासन ने जड़ा ताला

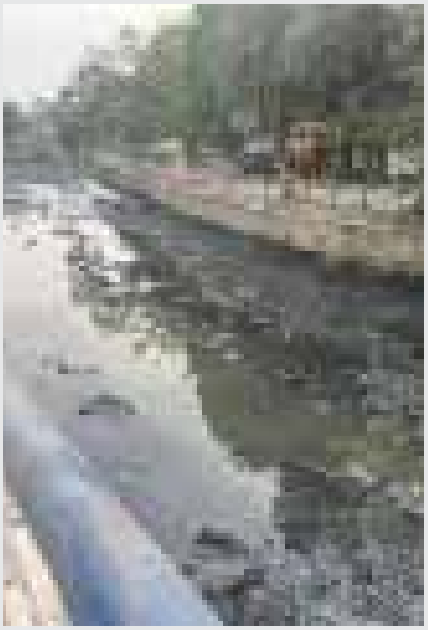

क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते प्रशासन ने कान्ह और सरस्वती नदी में बगैर ट्रीट किया हुआ सीवरेज का पानी छोड़ने वाली 9 फैक्ट्रियों की विद्युत सप्लाई बंद कर दी है। गौरतलब है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को सिटी बस कार्यालय के सभाकक्ष में नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें उन्होंने इंदौर की नदियों और नालों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कार्य नीति तैयार करने पर चर्चा की थी। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों को ऐसे उद्योग जो अपशिष्ट पदार्थ और सीवेज को बिना उपचार सीधे नदी और नालों में प्रवाहित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे।

बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि नदी और नालों को 2028 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इंदौर में एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यह एक्शन प्लान दो भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक दीर्घकालीन कार्य नीति होगी तथा एक अल्पकालीन कार्य नीति होगी। उन्होंने नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह को भी निर्देश दिए थे कि नमामि गंगे एवं अमृत 2.0 योजना अंतर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के साथ ही शहर में ऐसे अन्य नाले भी चिन्हांकित किए जाएं जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है।

ग्राम पंचायतों के लिए बनाई है ये योजना

बता दे कि इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में क्षिप्रा और कान्ह नदी के किनारे 62 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में 119 कम्युनिटी लीच पिट और 49 ग्रेवल फिल्टर लगाए जाएंगे ताकि नदी एवं नालों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। इसमें प्रत्येक ग्राम के लिए अलग कार्य नीति बनाई जाएगी।

सीएम नहीं रहो तो... होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग

भोपाल में आध्यात्मिक आंदोलन ब्रह्माकुमारीज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा कि जब हम दूसरों के लिए काम करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है। मेरे पास अभी भी समय नहीं है। मैं लगातार व्यस्त रहता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि कहा कि जब कोई व्यक्ति शीर्ष पद पर नहीं रहता है तो होर्डिंग्स से उसकी तस्वीरें 'गधे के सिर से सींग' की तरह गायब हो जाती हैं। भोपाल में आध्यात्मिक आंदोलन ब्रह्माकुमारीज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा कि जब हम दूसरों के लिए काम करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है। मेरे पास अभी भी समय नहीं है। मैं लगातार व्यस्त रहता हूं।

यह अच्छा है कि हमें राजनीति से दूर काम करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही शिवराज ने कहा कि मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं।' लेकिन रंग देखने वाले बहुत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप मुख्यमंत्री हैं, (ऐसे लोग कहते हैं) 'भाईसाहब आपके पैर और हाथ कमल की तरह हैं'। लेकिन जब कोई (मुख्यमंत्री पद पर) नहीं रहता तो (उसकी) तस्वीरें होर्डिंग्स से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग। 64 वर्षीय चौहान ने पिछले महीने मोहन यादव के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में 230 में से 163 सीटें जीतकर भारी जीत दर्ज करने के बाद यह परिवर्तन हुआ। कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चौहान ने चार बार राज्य की कमान संभालने के बाद सीएम पद खोने पर चुटकी ली है। हाल ही में बीजेपी नेता ने कहा था कि कभी-कभी राज्याभिषेक के बाद 'वनवास' पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार काम करेगी और किसानों से जो वादे किये गये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। नई सरकार 'लाडली बहना आवास योजना' जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। कुछ बड़े उद्देश्य होंगे, 'कई बार राज तिलक होने के बाद वनवास हो जाता है' लेकिन यह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है।

राहुल गांधी को लेकर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मणसिंह बोले

वे साधारण सांसद हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दें...

कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता एवं सांसद हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिये। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह शनिवार को मध्यप्रदेश के गुना में कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बयान देते हैं, तो उनका चेहरा टीवी पर कम दिखाया जाता है, तो इसपर सिंह ने कहा, ''राहुल गांधी एक सांसद हैं, वह (पार्टी के) अध्यक्ष नहीं हैं, और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''आप (मीडिया) लोगों को राहुल गांधी को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए और न ही हमें ऐसा करना चाहिए।''

पांच बार सांसद और तीन बार विधायक रह चुके लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी केवल एक सांसद हैं और वह पार्टी के बाकी सांसदों के बराबर हैं। उन्होंने कहा, ''कोई जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से (बड़ा) बनता है। राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता मत मानिए, मैं भी नहीं मानता। वह एक साधारण सांसद हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें तवज्जो देते हैं या नहीं।''

इस बारे में जब लक्ष्मण सिंह से रविवार को पूछा गया तो उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, ''हम सब पार्टी कार्यकर्ता हैं।'' पिछले महीने हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में गुना जिले की चचौरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका पेंची ने लक्ष्मण सिंह को 61,000 से अधिक मतों से हराया था।

साल के आखिरी दिन करीब तीन लाख भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन

ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में साल के आखिरी दिन रविवार को सामान्य दर्शन व्यवस्था लागू रही। श्रद्धालुओं की संख्या कम रहने से मंदिर प्रशासन ने 250 रुपये की शीघ्र दर्शन व्यवस्था को चालू रखा। दिनभर में करीब ढाई से तीन लाख भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए।प्रशासन को उम्मीद थी कि 31 दिसंबर व एक जनवरी को 10 लाख से अधिक भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे।

ऐसी रही दर्शन व्यवस्था

अधिकारियों ने इसी के अनुसार दर्शन व्यवस्था तय की थी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भीड़ अधिक होने पर 250 रुपये की शीघ्र दर्शन सुविधा को बंद रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही जनदबाव को देखते हुए दर्शनार्थियों को नवनिर्मित टनल एक व दो से प्रवेश देते हुए गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन की व्यवस्था निर्धारित की थी। हालांकि 31 दिसंबर को अनुमान के मुताबिक दर्शनार्थियों की संख्या काफी कम रही।

इससे पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भक्तों को दर्शन कराए गए। श्रद्धालुओं को पुराने फैसिलिटी सेंटर से कार्तिकेय व गणेश मंडप से भगवान के दर्शन सुलभ हुए। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि अगर एक जनवरी को भीड़ रही, तो नई दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी। रविवार जैसी सामान्य स्थिति रही तो पूर्व निर्धारित व्यवस्था को ही लागू रखा जाएगा।

अब 40 मिनट में होंगे भगवान महाकाल के दर्शन

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार व सोमवार को दो दिन में करीब 10 लाख श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे। अधिकारियों का दावा है कि भीड़ भरे इन दो दिनों में भक्तों को 40 मिनट में भगवान महाकाल के दर्शन कराए जाएंगे लेकिन जब तक गणेश व कार्तिकेय मंडपम में जनदबाव कम नहीं होगा भक्तों को शीघ्र दर्शन होने में संशय है। मंदिर प्रशासन को इन दोनों स्थानों से दर्शनार्थियों को शीघ्र बाहर निकालने की योजना बनानी चाहिए। महाकाल मंदिर में बीते रविवार को करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। अधिकारियों का अनुमान है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को 10 लाख से अधिक भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शनार्थियों को चारधाम मंदिर के सामने से प्रवेश दिया जाएगा। यहां से दर्शनार्थी त्रिवेणी संग्रहालय के समीप शक्ति पथ से होते हुए महाकाल महालोक, टनल 1 व 2 से होते हुए गणेश व कार्तिकेय मंडपम से भगवान के दर्शन करते हुए आपातकालीन द्वार से बाहर निकलेंगे। तय मार्ग काफी चौड़ा है : मंदिर समिति द्वारा जो मार्ग तय किया गया है, वह काफी चौड़ा है, इससे होते हुए श्रद्धालु तेजी से मंदिर के भीतर पहुंच जाएंगे लेकिन गणेश व कार्तिकेय मंडप में अलग-अलग कतार में दर्शन करते हुए आपातकालीन द्वार से बाहर निकलने में सर्वाधिक समय लगता है। यहां दर्शनार्थी काफी देर तक रुकते हैं।

वर्ष 2023 आधिकारिक तौर पर सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया : डब्ल्यूएमओ

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा, ''अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो 2023 'विनाशकारी भविष्य का एकमात्र पूर्वावलोकन' है जो हमारा इंतजार कर रहा है।'' उन्होंने कहा, मानव गतिविधियां पृथ्वी को झुलसा रही हैं। हमें रिकॉर्ड तोड़ तापमान वृद्धि का जवाब पथ-प्रदर्शक कार्रवाई से देना चाहिए। गुतारेस ने कहा, ''हम अभी भी सबसे खराब जलवायु आपदा से बच सकते हैं। लेकिन केवल तभी जब हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और जलवायु न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षा के साथ कार्य करें।'' डब्ल्यूएमओ ने कहा कि वह मार्च 2024 में अपनी अंतिम वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा, विस्थापन और स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विवरण शामिल होगा।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वैश्विक तापमान रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 2023 बड़े अंतर से अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। वार्षिक औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से बढ़ते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर जा रहा है, जोकि महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का लक्ष्य दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को इसी आंकड़े तक सीमित करना है। समझौते के अनुसार, दीर्घकालिक वृद्धि की गणना 2023 जैसे किसी विशिष्ट वर्ष के बजाय दशकों के औसत के रूप में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जून और दिसंबर के बीच हर महीने में वैश्विक तापमान का नया रिकॉर्ड बना तथा जुलाई और अगस्त को सबसे गर्म महीनों के रूप में दर्ज किया गया।

डब्ल्यूएमओ ने पाया कि वार्षिक औसत वैश्विक तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस था, जोकि पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक है। इसने वैश्विक तापमान की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले छह प्रमुख डेटासेट को समेकित किया, जिनमें से सभी ने 2023 को रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्थान दिया। डब्लूएमओ की महासचिव सेलेस्टे सौलो ने कहा, जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह हम सभी को प्रभावित कर रहा है, खासकर सबसे कमजोर लोगों को। उन्होंने कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हम पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन हमें और अधिक करना होगा तथा हमें इसे जल्दी करना होगा। हमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक परिवर्तन में तेजी लानी होगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा, ''अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो 2023 'विनाशकारी भविष्य का एकमात्र पूर्वावलोकन' है जो हमारा इंतजार कर रहा है।'' उन्होंने कहा, मानव गतिविधियां पृथ्वी को झुलसा रही हैं। हमें रिकॉर्ड तोड़ तापमान वृद्धि का जवाब पथ-प्रदर्शक कार्रवाई से देना चाहिए। गुतारेस ने कहा, ''हम अभी भी सबसे खराब जलवायु आपदा से बच सकते हैं। लेकिन केवल तभी जब हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और जलवायु न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षा के साथ कार्य करें।'' डब्ल्यूएमओ ने कहा कि वह मार्च 2024 में अपनी अंतिम वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा, विस्थापन और स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विवरण शामिल होगा।

10 फरवरी से इंदौर से अयोध्या तक चलेगी स्पेशल आस्था ट्रेन

अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इंदौर से स्पेशल आस्था ट्रेन 10 फरवरी से अयोध्या तक चलेगी। शुक्रवार रात में सोशल मीडिया एक्स पर रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने यह जानकारी पोस्ट की है। जनवरी से मार्च तक देशभर से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई जानी है। इंदौर से भी फरवरी में स्पेशल ट्रेन अयोध्या तक चलेगी। हालांकि अब तक इसका रूट तय नहीं हो सका है। रेल राज्य मंत्री के एक्स पर पोस्ट के अनुसार इंदौर के अलावा उधना (सूरत)-अयोध्या, मेहसाणा-सलारपुर, वापी-अयोध्या, वडोदरा-अयोध्या, वलसाड़-अयोध्या के बीच भी अलग-अलग तारीखों से स्पेशल यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। गौरतलब है कि इंदौर से अयोध्या तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही है। जनप्रतिनिधियों से लेकर कई संगठन सीधी ट्रेन शुरू करने की मांग कर चुके हैं।

आइआरसीटीसी कर सकता है संचालन

सूत्रों को कहना है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आइआरसीटीसी) द्वारा भी आस्था ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। आइआरसीटीसी वर्तमान में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। इसमें भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। संभावना है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की तरह ही आस्था ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। वैसे भी जनवरी से मार्च के बीच आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन होना है।

लंबे समय तक याद रखी जाएंगी 2023 की आर्थिक उपलब्धियां

वर्ष 2023 में भारतीय बैंकों विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों का स्तर लगभग न्यूनतम स्तर पर आ गया है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगभग उच्चत्तम स्तर पर आ गया है। कई बैंकों में तो यह स्तर अमेरिकी बैकों के पूजीं पर्याप्तता अनुपात से भी अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत के आसपास रहने की प्रबल सम्भावनाएं बन रही हैं। इस वर्ष की प्रथम तिमाही, अप्रैल-जून 2023, में आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत की रही है, वहीं द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितम्बर 2023 में 7.6 प्रतिशत की रही है। इसी प्रकार, दीपावली त्यौहार पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के चलते एवं अक्टोबर 2023 माह में विनिर्माण के क्षेत्र में विकास दर के 12 प्रतिशत से ऊपर रहने से इस वर्ष की तृतीय तिमाही, अक्टूबर-दिसम्बर 2023, में भी आर्थिक विकास 7 प्रतिशत रह सकती है। इससे पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने की प्रबल सम्भावनाए बन रही हैं। जबकि, विश्व के कई अन्य विकसित देशों में मंदी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार भारत वर्ष 2023 में भी लगातार विश्व की सबसे तेज गति से विकास करती अर्थव्यवस्था बना रहा।

भारत के आर्थिक विकास में लगातार गति आने से भारत में विदेशी निवेश की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 62,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। 8 दिसम्बर 2023 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 60,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर था, जो 15 दिसम्बर 2023 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 61,600 करोड़ अमेरकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया एवं 22 दिसम्बर 2023 को समाप्त सप्ताह में 62,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। इस प्रकार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि, अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर 64,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया था, अब शीघ्र ही इस उच्चत्तम स्तर को पार कर जाने की भरपूर सम्भावना व्यक्त की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान, भारतीय रुपए पर अत्यधिक दबाव आ गया था, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए को अवमूल्यन से बचाने एवं भारत रुपए के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकी डॉलर को भरपूर मात्रा में बाजार में बेचा था इससे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने से केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक को देश के आर्थिक विकास में गिरावट के चलते पैदा हुए किसी भी बाहरी एवं अंदरूनी वित्तीय अथवा आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलती हैं। यह आर्थिक मोर्चे पर संकट के समय देश को आरामदायक स्थिति उपलब्ध कराता है।

विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में अनिवासी भारतीयों ने रिकार्ड 12,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का प्रेषण भारत में किया है। अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई यह राशि पूरे विश्व में किसी भी देश को भेजी गई राशि में सर्वाधिक है। यह आर्थिक क्षेत्र में भारत की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है। विदेशी निवेशकों के साथ ही अनिवासी भारतीयों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर एवं खाड़ी के देशों में अनिवासी भारतीयों की भारी संख्या निवास करती है और केवल इन 4 देशों से ही 54 प्रतिशत प्रेषण भारत को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में अनिवासी भारतीयों द्वारा 11,110 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि भारत में प्रेषित की गई थी।

भारत आज विश्वभर के निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप विकसित हो गया है। विशेष रूप से केंद्र सरकार एवं कुछ राज्यों द्वारा की जा रही पहल विदेशी पूंजी को भारत में आकर्षित करती नजर आ रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत आज इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्वीट स्पॉट के रूप में दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी उत्पादन प्रोत्साहन योजना ने विदेशी निवेशकों की भारत में रुचि बढ़ा दी है। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में श्रम, कराधान और व्यापार परमिट जैसे क्षेत्रों में नियामक सुधारों से व्यापार करने में आसानी बढ़ी है। अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा और कुशल श्रम की उपलब्धता देश को निवेश के अन्य देशों के विकल्प के मामले में एक तरह की बढ़त देते हैं, जो विदेशी निवेशकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करते नजर आ रहे हैं।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अनुपालन प्रतिवेदन में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितंबर 2023, में भारत का चालू खाता घाटा 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत रह गया है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितम्बर 2022, में 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहते हुए सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत था।

महिला अग्निवीरों' की शिरकत से और सशक्त हुई नौसेना

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और जलीय निगरानी तंत्र में स्वदेशी जहाज, पनडुब्बी, आईएनएस विक्रांत, जलीय विमान, यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन, हमारी नौसेना की ताकत हैं। उनकी सुरक्षा अभेद है। पलक झपकते ही दुश्मन को पानी में डुबोने की हिम्मत रखती है।

नौसेना बलों की उपलब्धियां और राष्ट्र में उनके योगदान का वर्णन जितना किया जाए, उतना कम होगा। इसलिए भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी नौसेना की वाहवाही होती है। इसलिए क्योंकि वह दिनों दिन अपने नए-नए प्रयोगों से नित नई ऊंचाइयां छू रही है। इस कड़ी में अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है। नौसेना में आधी आबादी ने दस्तक दे दी है। इसी सीजन में एक हजार 'अग्निवीर महिला सैनिक' नौसेना में शामिल हुई हैं जिससे इस टुकडी की न सिर्फ ताकत बढ़ी, बल्कि उनके अनुशासन कार्यान्वयन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हुआ। आज'नौसेना दिवस'है इस बार ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें अब महिलाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित हो गई है। नौसेना में पहली मर्तबा 'नौसैनिक पोत' पर महिला कमांडिंग अधिकारी को नियुक्त किया गया। सरकार का ये कदम निश्चित रूप से अकल्पनीय और सराहनीय है। महिला सशक्तिकरण में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है।

बहरहाल, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और जलीय निगरानी तंत्र में स्वदेशी जहाज, पनडुब्बी, आईएनएस विक्रांत, जलीय विमान, यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन, हमारी नौसेना की ताकत हैं। उनकी सुरक्षा अभेद है। पलक झपकते ही दुश्मन को पानी में डुबोने की हिम्मत रखती है। नौसेना के इतिहास और आज के खास दिवस की बात करें, तो उसका एक सुनहरा युग हमने व्यतीत किया है। सन् 1971 के इंडो-पाक युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के शुरू होने कीं याद में हमारी सेना प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को 'नौसेना दिवस' का पर्व मनाती है। इंडियन नेवी की पूर्ण स्थापना की जहां तक बात है तो श्रीगणेश 1612 में हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 'रायल इंडियन नेवी' नाम से अपनी सेना बनाई थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कमर्शियल शिपों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस सैन्य का गठन किया था। पर, आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र व्यवस्था ने 1950 में भारतीय नौसेना के रूप में पुनर्गठित कर दिया।

नेवी डे समुद्री सीमाओं को सुरक्षित सहजने और जलीय ऑपरेशन व मिशनों को मुकम्मल करने के तौर पर भी याद किया जाता है। बंदरगाह की यात्राओं, विभिन्न देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास, परोपकारी मिशनों, समुद्री किनारों को सुरक्षा देना और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंधों पर होती है। नौसेना की अकल्पनीय भूमिका पर तो चर्चाएं होती ही है, उनकी देश भक्त निष्ठा जनमानस को सेना के प्रति आदर-सम्मान करना भी सिखाती है। देश का कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे अपनी सेना पर गर्व न होता हो। नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री प्रभाग है, जिसमें राष्ट्रपति कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करता है। बहरहाल, नौसेना के समझ इस वक्त कुछ चुनौतियां खड़ी हुई है। वो चुनौती चीन दे रहा है। दरअसल, चीन हमारे समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करने की फिराक में कई समय से घात लगाए बैठा हुआ है। ये सच है कि सेना से वास्ता रखने वाली ज्यादातर सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती, इसलिए कि इंटरनल सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। फिर भी अगर कोई सूचना सेना द्वारा देशवासियों को दी जाए, तो समझ लेना चाहिए, मामला गंभीर है। नौसेना को सूचना मिली है कि हिंद प्रशांत में चीन कभी भी कोई बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। ये बात पिछले ही सप्ताह खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताई। मसला वास्तव में गंभीर है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। चीन हिंद महासागर में अपनी सैन्य शक्तियों के माध्यम से भारतीय जलीय परिक्षेत्र में आक्रमण करने के मूड में है। हालांकि, कुछ एशिया देशों ने तो घुटने टेक भी दिए हैं। पाकिस्तान के जल क्षेत्र में वो खुलकर मनमानी कर रहा है। लेकिन उसकी भारतीय क्षेत्र में हिम्मत नहीं हो रही। उनको पता है भारतीय नौसेना उनका बुरा हाल कर देगी।

भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना मानी जाती है। इसलिए चाइना इंडियन नौसेना की ताकत को अच्छे से जानता-समझता है। जलीय महासागरों का इस्तेमाल किसी भी राष्ट्र की वैध आर्थिक आकांक्षाओं के लिए होता है। इस लिहाज से देखें तो चीन के पास आर्थिक गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहने का एक वैध कारण है। पर, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय नौसैनिक शक्ति के रूप में, वहां क्या हो रहा है, इस पर भारतीय नौसेना अगर नजर रखती है तो चीन चिड़ता है। वो चाहता, उसकी कोई पहरेदारी न करे, समुंद्री संपदा पर दंबगई से राज करता रहे। पाकिस्तान, ताइबान, नेपाल आदि मुल्क शांत रहते हैं, वैसी ही उम्मीद चीन भारत से करता है। लेकिन, भारतीय नौसैनिक हमेशा चौकन्नी रहती है। चीन भी जानता है कि उनकी छोटी सी भूल पर ही भारतीय सैनिक उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। इसलिए चीन फूंक-फूंक कर कदम रखता है।

सर्दियों में सेहत को दोगुना लाभ पहुंचाएंगे भीगे हुए काजू...

मिलेंगे ढेरों फायदे...

सर्दियों में खुद को स्वस्थ रखने के लिए कई लोग डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं। क्या आप भीगे हुए काजू के फायदों के बारे में जानते हैं। बता दें कि भीगे हुए काजू आपकी सेहत को दोगुना फायदा पहुंचा सकता है।

सर्दियों के मौसम में लोग खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इस मौसम में पहनावे से लेकर खानपान तक में बदलाव आता है। वहीं इस मौसम में लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। जिसके कारण लोग वायरल, इंफेक्शन या भी अन्य बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि खुद को हेल्दी रखने के लिए अपने खानपान का सही ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दें कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए कई लोग डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है। इन्हीं में से एक काजू है। जिसके सेवन से कई फायदे मिलते हैं। वहीं सर्दियों में भीगे हुए काजू आपकी सेहत को दोगुना फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी अब तक काजू के फायदों से अंजान थे, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसके फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।

बेहतर होगा पाचन

सर्दियों में बहुत सारे लोगों को पाचन संबंधी समस्या होती है। जिसके कारण उनके रोजमर्रा का काम प्रभावित होने लगता है। वहीं यदि आप भीगे हुए काजू का सेवन करते हैं, तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं में आराम मिल सकता है। बता दें कि भीगे हुए काजू मुश्किल घटकों को तोड़ने में मदद करते हैं। जिससे आपका पाचन बेहतर होता है।

मजबूत होगी इम्यूनिटी

इसके साथ ही सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जिसके कारण हमें आसानी से बीमारियां व संक्रमण घेर लेते हैं। ऐसे में अगर आप भीगे हुए काजू का सेवन करते हैं, तो यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। काजू में जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस मौसम में भीगे हुए काजू खाने से फ्लू और सर्दी से भी बचा जा सकता है।

स्किन के लिए हेल्दी

सर्दियों में सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि स्किन का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि सर्द हवाएं हमारी स्किन की नमी छीन लेती हैं। इसलिए आप स्किन को हेल्दी रखने के लिए भीगे काजू का सेवन कर सकती हैं। बता दें कि भीगे काजू में विटामिन ई, सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही यह आपको समय से पहले बूढ़े होने से बचाते हैं।

ब्लड शुगर होगा कंट्रोल

बता दें कि भीगे हुए काजू का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। क्योंकि भीगे हुए काजू में फाइबर की अच्छी मात्रा आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। साथ ही यह आपके एनर्जी लेवल को भी बनाए रखती है।

एनर्जी लेवल

काजू एक हेल्दी फैट का बढ़िया स्त्रोत है। इसमें मोनोअनसेचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है। यह फैट आपको पूरा दिन एनर्जी देते हैं। यह आपको काफी एनर्जी देता है।

अचानक हार्टबीट बढ़ने या कम होने के लक्षण को न करें नजरअंदाज

शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि आप हार्टबीट और हार्ट हेल्थ का विशेष ध्यान दें। हार्टबीट के अचानक से बढ़ जाने की स्थिति को आरेथमिया कहा जाता है। हार्ट बीट दिल संबंधी कई स्थितियों का संकेत देती है। किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने व स्वस्थ रहने के लिए उसके दिल की धड़कन का ठीक रहना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कई बार कुछ स्थितियों में दिल की धड़कन अचानक से तेज या फिर कम हो जाती है। हार्टबीट का अचानक से तेज व धीमा होना जैसे घबराहट, बेचैनी और चिंता आदि के कारण होता है। हांलाकि कई बार ऐसा होने के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर स्थिति होती है। आपको बता दें कि हार्टबीट के अचानक से बढ़ जाने की स्थिति को आरेथमिया कहा जाता है। यह समस्या उन लोगों को अक्सर होती है, जिनको सीरियस हार्ट कंडीशन का खतरा होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि आप हार्टबीट और हार्ट हेल्थ का विशेष ध्यान दें। अगर आपकी भी हार्टबीट अचानक से बढ़ जाती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अचानक से हार्टबीट क्यों बढ़ जाती है। साथ ही इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।

क्यों बढ़ती है हार्टबीट

खानपान और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, खराब सेहत, ड्रग्स का सेवन, शरीर में पानी की कमी और चिंता या डिप्रेशन की वजह से हार्ट बीट या हार्ट पल्पिटेशन अचानक से बढ़ जाती है। आसान भाषा में समझें तो हार्ट बीट दिल संबंधी कई स्थितियों का संकेत देती है। ऐसे में हार्टबीट का अचानक से बढ़ना या घटना इस बात का संकेत देता है कि आपको दिल संबंधी गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अचानक से हार्टबीट का बढ़ जाना सामान्य कंडीशन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट रेट 1 मिनट में 120 से ज्यादा होता है, तो इसको सामान्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बता दें कि हार्टबीट का असंतुलित होना शरीर में किसी सीरियस हार्ट कंडीशन का संकेत भी हो सकता है।

हार्टबीट बढ़ने के कारण

- टेंशन या डिप्रेशन के कारण
- ज्यादा एक्सरसाइज या रनिंग करने से
- बहुत ज्यादा तंबाकू, अल्कोहल व कैफीन आदि का सेवन करना
- हार्ट संबंधी बीमारी होने पर

जानिए क्या हैं उपाय

अचानक से हार्टबीट बढ़ने पर आपको सबसे पहले शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में घबराने या पैनिक होने से स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। वहीं परेशानी ज्यादा बढ़ने पर बिना देरी के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा नीचे बताए गए उपायों की मदद से भी आप अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं।

- अधिक गर्मी होने पर कम तापमान वाले स्थान पर बैठें।
- शांत रहने का प्रयास करें और गहरी-गहरी सांस लें।
- अचानक से उठने व दौड़ने की कोशिश न करें।
- पानी और लिक्विड ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए।

हार्टबीट या हार्ट रेट के अचानक से बढ़ जाने पर शांत रहने की कोशिश करें और चेहरे पर ठंडे पानी के छीटें डालें। तनाव कम लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पी लें। अगर यह सब करने के बाद भी चक्कर, सीने में दर्द या फिर कमजोरी आदि महसूस हो। तो बिना देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए।

डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लिए बेहद जरुरी है दवाईयों का सेवन

आजकल काफी अधिक रिसर्च होने के कारण दवाइयों से होने वाले साइडइफेक्ट काफी कम हो गए है। पहले कई बार दवाओं के सेवन से व्यक्ति में कई तरह के साइड इफैक्ट देखने को मिलते थे, जिसमें हाथ-पैर में कंपन होना, पार्किंसंस होना, आदि शामिल है। मेंटल हेल्थ से संबंधित बीमारियों का इलाज सही समय पर करना बेहद जरुरी होता है। खासतौर से डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए जरुरी है कि व्यक्ति बेहतर डॉक्टर से अपना समय पर इलाज करवाए ताकि स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके।

वहीं बदलते समय के साथ मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन या अन्य समस्याओं में दवाइयों के उपयोग में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। किसी समय में जिन दवाइयों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई थी वहीं अब ये काफी कम हो गई है। समय के साथ इन दवाइयों से होने वाले साइड इफैक्ट्स भी काफी मामूली हो गए है। माना जाता है कि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारी में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों को खाने से पीड़ित की परेशानी कम होती है।

डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य में दी जाने वाली दवाईयों के संबंध में चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकैट्रिस्ट डॉ. शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि समय में आए बदलाव के साथ ही दवाओं का असर भी अलग हो गया है। दवाई दिए जाने का तरीका भी बदला है। आजकल काफी अधिक रिसर्च होने के कारण दवाइयों से होने वाले साइडइफेक्ट काफी कम हो गए है। पहले कई बार दवाओं के सेवन से व्यक्ति में कई तरह के साइड इफैक्ट देखने को मिलते थे, जिसमें हाथ-पैर में कंपन होना, पार्किंसंस होना, आदि शामिल है। हालांकि समय के साथ दवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और रिसर्च की बदौलत पीड़ित मरीज को होने वाले साइड इफैक्ट काफी कम देखने को मिलते है। वैसे मानसिक रोगों के लिए दवाइयों पर रिसर्च आज भी जारी है मगर इसके साइड इफेक्ट किसी अन्य बीमारी की तरह ही देखने को मिलते है। इसमें वजन बढ़ना, हॉर्मोन्स में बदलाव होना शामिल है। मरीज अगर डाइट पर ध्यान ना दें तो भी दवाइयों के कुछ साइड इफैक्ट देखने को मिल सकते है। ऐसे में दवाइयों का सेवन जब भी मरीज शुरू करता है तो उसे नियमित रूप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होता है ताकि किसी गंभीर लक्षण पर डॉक्टर नजर रख सके।

दवाइयां जारी रखना जरुरी : कई गंभीर बीमारियों जैसे मेनिया, सिजोफ्रेनिया आदि में दवाईयों का सेवन मरीज को जीवनभर करना पड़ सकता है। ये दवाई भी उसी प्रकार हुई जैसे बीपी या शुगर की दवाई, तो मानसिक बीमारी की दवाई को लेकर आशंकित नहीं होना चाहिए।

बच्चों को बनाना चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग तो जरूर सिखाएं ये बातें

वर्तमान समय में पेरेंट्स और बच्चों के बीच इमोशनल और मेंटल कनेक्ट काफी कम देखने को मिलती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मेंटली मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको नीचे बताई गई 5 चीजें जरूर सिखानी चाहिए। वर्तमान समय में पेरेंट्स और बच्चों के बीच इमोशनल और मेंटल कनेक्ट काफी कम देखने को मिलती है। इसके पीछे का कारण बच्चों के लिए समय न निकाल पाना, पेरेंट्स के बीच बढ़ते झगड़े, माता-पिता का अलग-अलग रहना आदि कारण बच्चों के मेंटल हेल्थ पर काफी गहरा असर छोड़ता है। इन वजहों से बच्चा कहीं न कहीं मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस कारण बच्चे छोटी-छोटी बातें भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं।

आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को बहुत जल्दी या छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो वहीं कुछ बच्चे थोड़ा डरे व सहमे लगते हैं। बता दें कि इन सारी चीजों का सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चों का मानसिक विकास कमजोर है। ऐसे में अगर आप भी पेरेंट्स हैं और अपने बच्चें को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप भी अपने बच्चे को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं।

असफलता को मैनेज करना

खेलकूद एक ऐसी चीज होती है, जिससे बच्चे हार व जीत का फर्क समझते हैं। ऐसे में हार मिलने के बाद उनको कैसे संभलना चाहिए, यह सीखने में स्पोर्ट्स उनकी काफी मदद करता है। इसके अलावा एक टीम के साथ मिलकर किस तरह से चीजें मैनेज की जाती हैं, यह भी बच्चे स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं। ऐसे में आप क्रिकेट, फूटबॉल, या बच्चे की पसंद का कोई भी खेल खेलने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही उनके हारने पर उसे कैसे मैनेज करना है, यह भी सिखा सकते हैं।

म्यूजिक से कम होगी एंजाइटी

बच्चों के अंदर से एंजाइटी और टेंशन को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूजिक होता है। क्योंकि यह बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायक हो सकता है। वहीं म्यूजिक की मदद से बच्चे का दिमाग भी शार्प हो सकता है।

ड्राइंग से बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस

बच्चे अपने अंदर की भावनाओं को ड्राइंग की मदद से आसानी से व्यक्त कर पाते हैं। इससे उनके अंदर का स्ट्रेस भी कम होता है। ऐसे में अगर बच्चे कम उम्र में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो यह आगे चलकर उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में बच्चे के आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने में ड्राइंग उनकी मदद कर सकती है।

मजबूत बनाएगी बागवानी

एक बीज से पौधा और पौधे से फल देने वाला पेड़ बनते देखना बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर ला सकता है। ऐसा करते हुए देखना उनके अंदर धैर्य को जन्म देता है और साथ ही किसी भी चीज की देखभाल का तरीका सीखने में मदद मिलती है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बागवानी के काम भी करने को दे सकते हैं।

स्ट्रेस को कम करता है डांस

बता दें कि डांस एक तरह का वर्कआउट होता है। इसको करने से बच्चा तनावमुक्त रह सकता है। अगर बच्चे को डांस करने में इंट्रेस्ट है, तो यह उनको खुश भी कर सकता है। इसलिए आप बच्चे को उनकी पसंद के मुताबिक कोई भी डांस फोम सीखने व करने दें। जिससे कि वह स्ट्रेस फ्री रहने के साथ मेंटली फिट भी रहें।

भगवान श्रीराम के जीवन की साक्षी रही है सरयू नदी

पाप और अशुद्धियों को करती है दूर

अयोध्या से होकर बहने वाली सरयू नदी प्रभु श्रीराम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी और बैकुंठगमन तक की साक्षी रही है। सरयू नदी का नाम सुनते ही मन प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या पहुंच जाता है। देश में गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का अपना महत्व है। तो वहीं सरयू नदी प्रभु श्रीराम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी और बैकुंठगमन तक साक्षी बनी। नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास, पहचान व महत्व रहा है। सरयू नदी का नाम सुनते ही मन प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या पहुंच जाता है। ऐसे में एक बार फिर सरयू नदी अयोध्या के राम मंदिर की साक्षी बन रही है। तो आइए जानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से सरयू नदी का संबंध और इसका महत्व

सरयू का योगदान

हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सरयू नदी किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में सरयू नदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी से यह नदी होकर बहती है। अयोध्या को भगवान श्रीराम की नगरी भी कहा जाता है। वहीं अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने में भी सरयू नदी का काफी योगदान है। वास्तव में सरयू नदी से अयोध्या काफी समृद्ध है। इसके अलावा अयोध्या एक पर्यटन स्थल के रूप में भी सामने आया है। ऐसे में सरयू नदी के तट पर बसी श्री राम की नगरी अयोध्या में कई पर्यटक स्थल हैं।

सरयू का उल्लेख

ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख मिलता है। सरयू नदी अयोध्या शहर के पास बहती थी। श्रीराम को भगवान श्रीहरि विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस घटना का भी उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ द्वारा सरयू नदी के तट पर दुर्घटनावश श्रवण कुमार की हत्या कर दी गई थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि धरती के नीचे बहने वाली यह एकमात्र नदी है। अयोध्या में बहने वाली यह पवित्र नदी शहर की अशुद्धियों और पापों को धोती है। कई धार्मिक मौकों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं।

सरयू के पास हैं कई पवित्र स्थल : वैसे तो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घूमने के लिए काफी कुछ है। हजारों-लाखों की संख्या में पर्यटक पूरे साल अयोध्या घूमने के लिए आते हैं।

राम जन्मभूमि

अयोध्या प्रांत के सबसे शानदार और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण सह तीर्थ स्थलों में प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भारत का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयोध्या हिंदूओं की पवित्र भूमि मानी जाती है।

हनुमान गढ़ी मंदिर

अयोध्या में राम मंदिर के बाद अगला सबसे अहम मंदिर हनुमान गढ़ी है। यह शहर के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित है। यहां से आप अयोध्या के कुछ बेहतरीन दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्रीराम के दौरान इस स्थान पर उनके परम भक्त हनुमान का घर भी हुआ करता है। भारत की सबसे प्रमुख नदियों में शामिल सरयू नदी अपने आप में कई विविधताओं को समेटे हुए है।

कीवी से बनाएं एंटी-एजिंग फेस पैक और पाएं यंगर स्किन...

ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के अलावा आपको कुछ होम रेमिडीज को भी जरूर अपनानी चाहिए। इन्हीं में से एक है कीवी फेस पैक। विटामिन सी रिच कीवी से बनने वाले फेस पैक ना केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग व इवन टोन बनाते हैं, बल्कि इससे आपकी स्किन अधिक यूथफुल भी नजर आती है।

हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन लंबे समय तक यूं ही जवां-जवां नजर आए। हालांकि, इसके लिए स्किन की सही तरह से देखभाल करना बेहद जरूरी है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के अलावा आपको कुछ होम रेमिडीज को भी जरूर अपनाना चाहिए। इन्हीं में से एक है कीवी फेस पैक। विटामिन सी रिच कीवी से बनने वाले फेस पैक ना केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग व इवन टोन बनाते हैं, बल्कि इससे आपकी स्किन अधिक यूथफुल भी नजर आती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कीवी की मदद से बनने वाले कुछ एंटी-एजिंग फेस पैक के बारे में बता रहे हैं-

कीवी और दही फेस पैक

कीवी को दही के साथ मिक्स करके एंटी-एजिंग फेस पैक बनाया जा सकता है।

आवश्यक सामग्री

- एक पका हुआ कीवी
- दो चम्मच दही

इस्तेमाल का तरीका

- सबसे पहले एक पकी हुई कीवी को मैश करें।
- अब इसमें दो बड़े चम्मच सादा दही मिलाएं।
- अपने फेस को क्लीन करें और इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
- करीबन 15 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें।

कीवी और केले फेस पैक

कीवी और केले का फेस पैक आपकी स्किन को टाइटन करने में मदद करता है। केला विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है जो स्किन को पोषित करता है।

आवश्यक सामग्री

- आधा पका हुआ केला
- एक कीवी

इस्तेमाल करने का तरीक

- केले और कीवी को एक साथ मैश कर लें।
- अब अपनी स्किन को क्लीन करके इस पेस्ट को अपने चेहरे व गर्दन पर लगाएं।
- करीबन 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें।

कीवी और एवोकाडो फेस पैक

कीवी के साथ एवोकाडो को मिक्स करके भी फेस पैक बनाया जा सकता है। एवोकाडो हेल्दी फैट और विटामिन से भरपूर होता है, जो आपकी स्किन को पोषित और हाइड्रेट कर सकता है।

आवश्यक सामग्री

- एक पकी कीवी
- आधा एवोकाडो

इस्तेमाल का तरीका-

- कीवी और एवोकैडो को एक साथ मैश कर लें।
- इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
- इसे धोने से पहले 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें।

सर्दियों में रूखे हो जाते हैं नाखून तो ऐसे रखें इनका ख्याल

आपने देखा होगा कि सर्दियों में नाखून काफी रूखे हो जाते हैं। इस कारण नाखूनों का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। आज हम आपको नाखूनों की देखभाल के कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन टिप्स को फॉलो कर अपने नेल्स का ध्यान रख सकती हैं।

सर्दियों का मौसम लगभग हर किसी को पसंद है। क्योंकि घूमने-फिरने से लेकर खाने-पीने तक के लिए सर्दियों का मौसम परफेक्ट होता है। लेकिन इस मौसम में अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा न करने पर इची स्कैल्प, त्वचा का रूखापन, बाल झड़ना आदि की समस्या होने लगती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा और बालों का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है।

लेकिन बालों और त्वचा का ख्याल रखते-रखते हम शरीर के दूसरे जरूरी अंगों के बारे में भूल जाते हैं। वह हमारे नाखून हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में नाखून काफी रूखे हो जाते हैं। इस कारण नाखूनों का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप अपने नाखूनों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यह टूटने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको नाखूनों की देखभाल के कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी इन टिप्स को फॉलो कर आप अपने नेल्स का ध्यान रख सकती हैं।

मॉइस्चराइज करना है जरूरी : सर्दियों के मौसम में नाखून ड्राई हो जाते हैं। ऐसे में नाखूनों की नमी को बरकरार रखने के लिए आप बादाम या फिर नारियल के तेल से अपने नाखूनों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं।

बेस कोट लगाएं : अपने नाखूनों पर आपको हमेशा बेस कोट लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके नेल्स धूल और गंदगी से बचे रहेंगे। साथ ही आपके नाखून भी इससे मजबूत होंगे।

क्यूटिकल क्रीम : कई बार नाखून साफ करने के दौरान क्यूटिकल्स को काट देते हैं। लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। बता दें कि क्यूटिकल्स को काटने की जगह उस पर लोशन या फिर क्यूटिकल क्रीम अप्लाई कर उनका ख्याल रखना चाहिए।

नेल मास्क: अगर आप अच्छे तरीके से नाखूनों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप नींबू के साथ बेकिंग सोडा या अंडे और शहद को मिलाकर अपने नाखूनों पर लगाएं। यह नाखूनों के लिए काफी अच्छा नेल मास्क है।

भारतीय कुश्ती में नया विवाद

बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ पहलवान जुटे

आर्य समाज अखाड़े के विवेक मलिक ने कहा ,' इन जूनियर पहलवानों का पूरा एक साल खराब हो गया। नये डब्ल्यूएफआई ने इन पहलवानों के भले के लिये फैसला लिया था जो जिला या प्रदेश स्तर की स्पर्धा भी नहीं खेल सके हैं। उन्होंने कहा , नये महासंघ को भी निलंबित कर दिया गया। इसका चुनाव अदालत के निर्देशों के अनुसार हुआ था लेकिन इसे काम नहीं करने दिया गया। निलंबन हटना चाहिये और महासंघ को काम करने देना चाहिये। इन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने मांग की है कि निलंबित डब्ल्यूएफआई को फिर बहाल किया जाये और तदर्थ समिति को भंग किया जाये।

भारतीय कुश्ती में जारी संकट में बुधवार को नया मोड़ आया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिये शीर्ष पहलवानों बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे। इनमें से करीब 300 बागपत के छपरौली के आर्य समाज अखाड़े से थे जबकि कई नरेला की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से भी थे। सुरक्षाकर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई। ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर तीनों पहलवानों की तस्वीरों के साथ लिखा था, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी , बजरंग और फोगाट।

भारतीय कुश्ती महासंघ के नये पदाधिकारियों के चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 चैम्पियनशिप गोंडा में कराने का फैसला किया गया जिसके बाद मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया और ये टूर्नामेंट भी रद्द हो गए। प्रदर्शनकारी पहलवानों में से कइयों के पास आखिरी बार जूनियर स्तर पर खेलने का मौका था। मुजफ्फरनगर स्टेडियम के कोच प्रदीप कुमार ने कहा ,उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक अखाड़े इस प्रदर्शन में हमारे साथ हैं। एक तरफ सिर्फ तीन पहलवान है और दूसरी तरफ लाखों हैं। उन्होंने देश के लाखों पहलवानों का कैरियर खराब कर दिया। उन्होंने कहा , इन लोगों के मन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की कोई इज्जत नहीं है। उन्हें सड़क पर पटक रहे हैं। बजरंग और विनेश ने अपने सरकारी सम्मान लौटा दिये हैं।

प्रदीप ने कहा, वे कहते आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई महिला और जूनियर पहलवानों के लिये हें लेकिन उन्होंने लाखों के कैरियर बर्बाद कर दिया। उनका प्रदर्शन डब्ल्यूएफआई में शीर्ष पद पाने के लिये है। एक बार ऐसा होने पर उनका सारा प्रदर्शन बंद हो जायेगा। करीब एक साल पहले जंतर मंतर पर ही ये तीनों शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे थे। उस समय किसान समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, महिला संगठनों और पहलवानों ने इनका समर्थन किया था। जनवरी 2023 से राष्ट्रीय शिविर और प्रतिस्पर्धायें ठप पड़ी है। डब्ल्यूएफआई दो बार निलंबित हो चुका है और तदर्थ समिति खेल का संचालन कर रही है।

आर्य समाज अखाड़े के विवेक मलिक ने कहा ,' इन जूनियर पहलवानों का पूरा एक साल खराब हो गया। नये डब्ल्यूएफआई ने इन पहलवानों के भले के लिये फैसला लिया था जो जिला या प्रदेश स्तर की स्पर्धा भी नहीं खेल सके हैं। उन्होंने कहा , नये महासंघ को भी निलंबित कर दिया गया। इसका चुनाव अदालत के निर्देशों के अनुसार हुआ था लेकिन इसे काम नहीं करने दिया गया। निलंबन हटना चाहिये और महासंघ को काम करने देना चाहिये। इन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने मांग की है कि निलंबित डब्ल्यूएफआई को फिर बहाल किया जाये और तदर्थ समिति को भंग किया जाये।

ये सितारे सोशल मीडिया से करते हैं परहेज...

बॉलीवुड के सितारों से लेकर आम आदमी तक, मौजूदा समय में लगभग हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। फिल्मी सितारे अपनी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर इन सितारों के लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं और इन्हें पोस्ट साझा करने के अलग से पैसे भी मिलते हैं। वहीं, कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं। उनको अपनी निजी बातें यूं पब्लिक के साथ साझा करना पसंद नहीं है।

रेखा : इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रेखा का है। अपने जमाने की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा आज भी किसी सोशल मीडिया साइट पर नहीं हैं। बॉलीवुड की तमाम अवॉर्ड फंक्शन की जान और अपनी अलग स्टाइल के लिए जानी जाने वाली रेखा, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेखा को अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कोई अकाउंट नहीं बनाया है।

रानी मुखर्जी : 'कुछ-कुछ होता है' से लेकर 'मर्दानी' जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली, रानी मुखर्जी को भी सोशल मीडिया पसंद नहीं है। पिछले दिनों 'कॉफी विद करण सीजन 8 ' में रानी कहा था, 'मैं फोन से जितनी दूरी हो सके, बनाए रखना चाहती हूं। मुझे अपने बारे में या अपनी बेटी के बारे में दुनिया को हर अपडेट देना पसंद नहीं है।' गौरतलब है कि आज तक रानी मुखर्जी की बेटी की तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर नहीं साझा की गई है।

जया बच्चन : एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वहीं, उनकी पत्नी और अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा जया बच्चन आज भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें सोशल मीडिया पर समय बिताना, समय की बर्बादी लगती है।

सैफ अली खान : सैफ अली खान ने भी सोशल मीडिया से आज तक दुरी बनाए रखी है। सोशल मीडिया पर उनको अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन उनके ठीक विपरीत उनकी पत्नी और बॉलीवुड स्टार करीना कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। करीना अपनी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खुशी को अपने फैंस के साथ साझा करती हैं। अपने दोनों बेटों की तस्वीरों के अलावा, करीना सैफ अली खान की भी तस्वीरें और उनसे जुड़ी बातों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताती रहती हैं।

रणबीर कपूर : इस लिस्ट में 'एनिमल' स्टार रणबीर कपूर का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स और 'कॉफी विद करण' के कई एपिसोड में इस बात पर कितनी बार चर्चा हुई है कि रणबीर कपूर फेक आईडी से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। रणबीर कपूर को भी अपनी प्राइवेसी काफी पसंद है और उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी शेयर करना सही नहीं लगता है।

दीया ने किए दिलचस्प खुलासे, बोलीं- 'फर्जी खबरों से जूझते हैं कलाकार'

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में खास जगह बनाई हैं। अभिनेत्री होने के साथ-साथ वे प्रकृति के भी काफी करीब हैं और अक्सर पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करती नजर आती हैं। हाल ही में, एक बातचीत के दौरान दीया ने अपने करियर के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने फर्जी खबरों पर चिंता जाहिर की।

दीया से जब पूछा गया कि क्या वे अपनी फिल्मी यात्रा के किसी हिस्से को बदलना चाहेंगी? अभिनेत्री ने जवाब देते हुए कहा, 'मैं इंडस्ट्री में बिना किसी तैयारी के आई थी। इंडस्ट्री में आकर ही मैंने काम करना सीखा है। हालांकि, मैं अपनी खूबियां जानती थी। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छी शिक्षा और आवाज का सही होना जरूरी है, यही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। मेरे करियर के शुरुआती आठ से दस वर्ष मुझे खुद को निखारने में लगे हैं'। अभिनेत्री से आगे पूछा गया कि इंडस्ट्री में वह कौन सी चीज है, जो आपको पसंद नहीं है? दीया ने जवाब देते हुए कहा, 'सिनेमा में फर्जी खबरे सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं। इंडस्ट्री में कलाकारों को फर्जी खबरों से जूझना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।' उन्होंने अपनी असुरक्षाओं के बारे में बात करते हुए कहा, 'असुरक्षा का डर तो बचपन से बना रहता है। जब मैं छोटी थी, तो खोने का डर रहता था। वहीं, बड़ी हुई, तो रिजेक्शन का डर और अब एक उम्रदराज उद्योग में अवसर खोने का डर बना रहता है।' दीया मिर्जा के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री आखिरी बार रत्ना पाठक शाह, फातिमा सना शेख और संजना सांघी के साथ फिल्म 'धक धक' में नजर आई थीं। इसके अलावा दीया अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म 'भीड़' का भी हिस्सा थीं। वे ओटीटी शो 'मेड इन हेवन' के दूसरे सीजन में भी नजर आई थीं।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

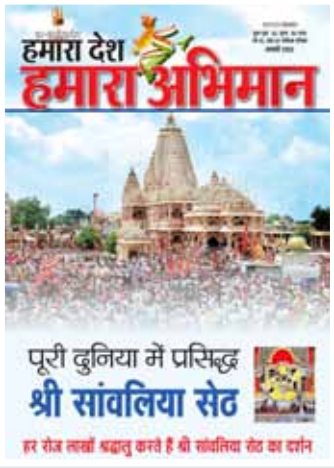

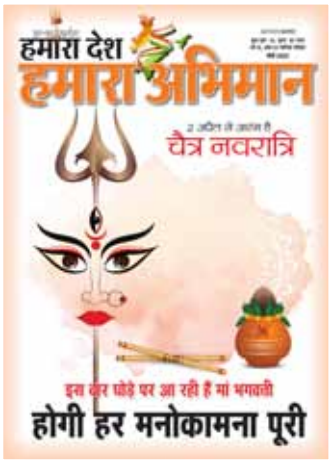

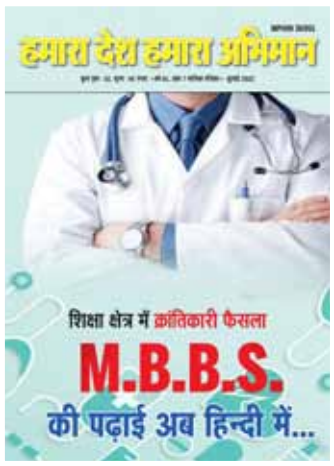

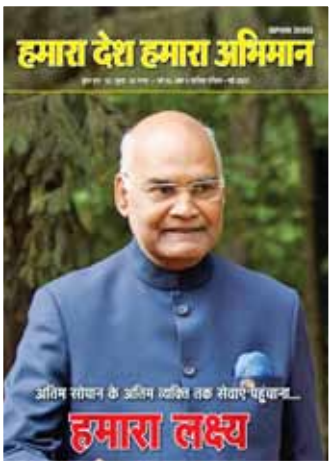

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः।
सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे।।

अर्थ : भगवान शिव शंकर जो पर्वतराज हिमालय के नजदीक पवित्र मन्दाकिनी के तट पर स्थित केदारखण्ड नामक श्रृंग में निवास करते हैं और हमेशा ऋषि मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं। जिनकी यक्ष-किन्नर, नाग व देवता-असुर आदि भी हमेशा पूजा करते हैं उन अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव शंकर की मैं स्तुति करता हूँ।